CNews सिटी चीफ

वर्ष-15, अंक-234
पृष्ठ-8 मूल्य 2 रूपया

सिटी चीफ

इंदौर, शुक्रवार 29 नवम्बर 2024

सम्पूर्ण भारत मे चर्चित हिन्दी अखबार

CITYCHIEFSENDMENEWS@GMAIL.COM

सुविचार

' जितना कठिन संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी.'

सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जजों से संपत्ति सार्वजनिक नहीं करेगी सरकार

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने गुरुवार को राज्यसभा को बताया कि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जजों से उनकी संपत्ति के विवरण को सार्वजनिक करने के लिए कोई नया कानून लाने की योजना नहीं है, जैसा कि एक संसदीय समिति ने सिफारिश की थी। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने एक लिखित जवाब में कहा कि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जजों की संपत्ति का विवरण केंद्र सरकार के पास नहीं रखा जाता है। दरअसल, सवाल पूछा गया था कि क्या सरकार सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जजों से उनकी उनकी संपत्ति का विवरण देने के लिए एक कानून लाने पर विचार कर रही है, जैसा कि अगस्त 2023 में संसद की स्थायी समिति की 'न्यायिक प्रक्रियाएं और उनमें सुधार' शीर्षक वाली रिपोर्ट में सिफारिश की गई थी। मंत्री ने इसका जवाब नहीं में दिया। मेघवाल ने यह भी कहा कि 'न्यायिक जीवन के मूल्य की पुनरावृत्ति' नामक दस्तावेज को सुप्रीम कोर्ट की पूर्ण पीठ ने सात मई 1997 को अपनाया था। इस दस्तावेज ने सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जजों के लिए कुछ न्यायिक मानक तय किए थे। इसके अलावा, 26 अगस्त 2009 को सुप्रीम कोर्ट की पूर्ण पीठ ने यह फैसला लिया था कि जजों द्वारा जमा की गई संपत्ति का विवरण सार्वजनिक किया जाएगा और इसे सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर प्रकाशित करने का प्रस्ताव रखा था। मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि 8 सितंबर 2009 को हुई बैठक में यह फैसला लिया गया कि संपत्ति का विवरण 31 अक्टूबर 2009 तक सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा। इसे स्वैच्छित प्रक्रिया में रखा गया। यानी यह केवल एक विकल्प था, जिसमें जज अपनी संपत्ति का विवरण वेबसाइट पर डालने के लिए स्वतंत्र थे।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा- दहेज प्रताड़ना में पति के दूर के रिश्तेदारों को बेवजह न लपेटे

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने अदालतों को इस बात को लेकर सचेत किया है कि दहेज प्रताड़ना के आरोपों के मामले को गहन तरीके से परीक्षण किया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि पति के दूर के रिश्तेदारों को उसमें बिना कारण न लपेटा जाए। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सीटी रविकुमार ने पति के कजन और उनकी पत्नी (कजन ब्रदर और उनकी पत्नी) के खिलाफ चल रहे क्रिमिनल केस को खारिज करते हुए यह व्यवस्था दी है। इस मामले में महिला के पिता ने दहेज प्रताड़ना की शिकायत की थी और महिला के ससुरालियों के खिलाफ दहेज प्रताड़ना की धारा-498ए के तहत केस दर्ज किया गया था। सुप्रीम कोर्ट में याचिकार्ताओं ने अर्जी दाखिल कर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज केस खारिज करने से मना कर दिया था। शीर्ष अदालत ने सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ टिप्पणी की और कहा कि हाई कोर्ट के सामने जब ऐसे मामले आए, जिसमें पति के दूर के रिश्तेदार आरोपी बनाए गए हों तो से ज्यादा सचेत रहकर मामले को एग्जामिन करना चाहिए।

मुकदमे सभी संबंधितों के लिए भारी कष्ट का कारण सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के संदर्भ में प्रीति गुप्ता बनाम राज्य झारखंड मामले में शीर्ष अदालत के फैसले में की गई टिप्पणी का उल्लेख किया, जिसमें कहा गया था कि आपराधिक मुकदमे सभी संबंधितों के लिए भारी कष्ट का कारण बनते हैं। यहां तक कि मुकदमे में अंतिम रूप से आरोपी का बरी होना भी अपमान के गहरे घावों को मिटा नहीं सकता। शीर्ष अदालत ने कहा कि यह टिप्पणी दरअसल यह चेतावनी थी कि पति के परिवार के किसी करीबी रिश्तेदार के अलावा अन्य किसी व्यक्ति को आरोपी बनाए जाने की स्थिति में यह देखना अदालत की जिम्मेदारी है कि क्या आरोप बढ़ा-चढ़ाकर लगाए गए हैं या फिर बिना कारण ज्यादा लोगों को इसमें आरोपी के तौर पर शामिल तो नहीं किया गया?

रिलेटिव शब्द को परिभाषित करें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रिलेटिव यानी रिश्तेदार शब्द को कानून में अलग से परिभाषित नहीं किया गया है और इसे सामान्य समझ के अनुसार परिभाषित किया जाना चाहिए। आमतौर पर इसे पिता, माता, पति या पत्नी, पुत्र, पुत्री, भाई, बहन, भतीजा, भतीजी, पोता या पोती या किसी व्यक्ति के जीवनसाथी को शामिल करते हुए समझा जा सकता है। जब आरोप किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ हो जो ब्लड, विवाह या गोद लेने के माध्यम से संबंधित नहीं है, तो अदालतों का कर्तव्य है कि वह परीक्षण करें कि आरोप बढ़ा-चढ़ाकर लगाए गए हैं या नहीं? अदालत ने गीता मेहरोत्रा बनाम राज्य यूपी मामले का भी उल्लेख किया, जिसमें यह कहा गया था कि पारिवारिक विवाद में नामों का केवल साधारण संदर्भ बिना सक्रिय भूमिका के आरोप के रूप में अदालत की ओर से संज्ञान लेने को उचित नहीं ठहराता।

ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन

नई दिल्ली। ऑस्ट्रेलिया की संसद ने के 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगान वाले कानून पारित कर दिया है। संघीय संसद के उच्च सदन सीनेट ने आज (गुरुवार को) इस विधेयक को पारित किया। निचली सदन हाउस ऑफ रिप्रिजेंटेटिव इसे एक दिन पहले ही पारित कर चुका है। अब जल्द ही यह दुनिया का ऐसा पहला कानून बन जाएगा और इसके साथ ऑस्ट्रेलिया ऐसा कानून लागू करने वाला पहला देश बन जाएगा। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि यह कानून 16 साल के कम आयु वर्ग के बच्चों को टिकटॉक, फेसबुक, स्नैपचैट, रेडिट, एक्स और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने से रोकेगा। विधेयक में प्रावधान किए गए नियमों के मुताबिक, प्रतिबंधित आयु वर्ग के लोगों का सोशल मीडिया अकाउंट को रोक पाने में जिम्मेदार रहने वाली कंपनियों पर 50 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर यानी करीब 275 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है। विधेयक में कहा गया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को दंड से राहत देने और प्रतिबंधों को लागू करने के तरीके पर विचार करने और उसे प्रभावी करने के लिए एक साल का ग्रेस पीरियड दिया जाएगा। विधेयक में यूजर्स की गोपनीयता और निजता की सुरक्षा को लेकर भी कानून बनाए गए हैं और कहा गया है कि किसी भी यूजर को बाध्यकारी तौर पर किसी भी तरह का पहचान पत्र (ड्राइविंग लाइसेंस या सरकार द्वारा जारी कोई भी आईडी) देने को मजबूर नहीं किया जा सकता है। इस विधेयक के पारित होने पर फेसबुक और इंस्टाग्राम की मालिकाना हक वाली कंपनी मेटा ने ऐतराज जताया है और कहा है कि विधेयक जल्दबाजी और हड़बड़ी में पारित किया गया है।

हाथ में संविधान की कॉपी लेकर प्रियंका गांधी ने ली सांसद के तौर पर शपथ

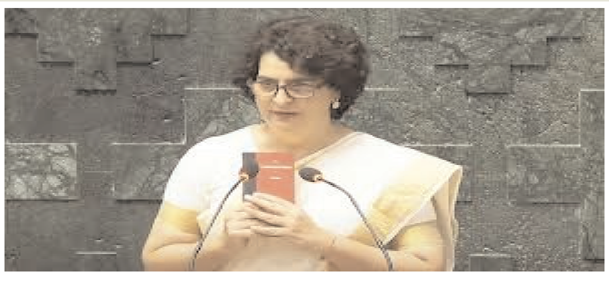

नई दिल्ली। वायनाड लोकसभा सीट से चुनी गईं प्रियंका गांधी ने गुरुवार को सांसद के तौर पर शपथ ली। कांग्रेस की नेता शपथ के दौरान हाथ में संविधान की कॉपी लिए रहीं। इस तरह उन्होंने संविधान वाले दांव को भी शपथ के साथ ही चलने की कोशिश की, जिस पर कांग्रेस समेत विपक्ष ने लोकसभा चुनाव के दौरान नैरेटिव तैयार किया था। लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस एवं अन्य विपक्षी दलों ने आरोप लगाया था कि सरकार इसलिए 400 सीट चाहती है ताकि संविधान बदला जा सके और गरीबों का आरक्षण छीन लिया जाए। इसके बाद जब लोकसभा का सत्र शुरू हुआ तो कांग्रेस के सांसदों ने संविधान लेकर ही शपथ ली थी। अखिलेश यादव और अवधेश प्रसाद जैसे नेता भी संविधान की कॉपी लिए दिखे। उसी को अब प्रियंका गांधी ने भी आगे बढ़ाया है। प्रियंका गांधी की शपथ के मौके पर उनके पति रॉबर्ट वाड्रा, बेटे रिहान वाड्रा और बेटी मिराया वाड्रा भी लोकसभा पहुंचे। इसके अलावा उनकी मां सोनिया गांधी और भाई राहुल गांधी पहले से ही सदन में मौजूद थे। राहुल गांधी खुद रायबरेली लोकसभा सीट से सांसद हैं, जबकि सोनिया गांधी राज्यसभा की मेंबर हैं। प्रियंका गांधी ने वायनाड लोकसभा सीट का उपचुनाव 4 लाख 10 हजार से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की है। उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के प्रत्याशी सत्यन मोकेरी को मात देकर लोकसभा में एंट्री की है। यहां से भाजपा ने नव्या हरिदास को चुनाव में उतारा था। बुधवार को ही अपने निर्वाचन का सर्टिफिकेट प्रियंका गांधी ने लिया था और कहा था कि यह हमारी मेहनत, प्यार और जनता के भरोसे की जीत है।

सीएम डॉ. मोहन यादव ने जर्मनी में रोजगार के लिए प्रदेश के युवाओं के सामने आ रही भाषाई चुनौती का निकाला हल

मध्यप्रदेश में खोलेंगे जर्मन भाषा के इंस्टीट्यूट, मिलेंगे रोजगार

म्यूनिख। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपनी यूके यात्रा के बाद अब जर्मनी के दौरे पर हैं। जर्मनी के म्यूनिख में उनका शानदार स्वागत हुआ, जहां उन्होंने जर्मन भाषा के इंस्टीट्यूट खोलने की घोषणा की। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गुरुवार को जर्मनी दौरे पर बावेरिया राज्य के चांसलरी प्रमुख और संघीय एवं यूरोपीय मामलों के साथ मीडिया विभाग के मंत्री डॉ. फ्लोरियन हेरमैन से मुलाकात की, जहां दोनों नेताओं ने आपसी सहयोग को और मजबूत करने के तरीकों पर विचार किया। सीएम ने कहा कि 8.50 करोड़ की जनसंख्या वाला देश जर्मनी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तकनीकी दक्षता के साथ जिस रूप में दुनिया के सामने उभरा वह आदर्श है। उन्होंने कहा कि जर्मनी की तकनीकी उन्नति विशेष रूप से ऑटोमोटिव सेक्टर में हमारे उद्योगों के लिए लाभकारी हो सकती है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि जर्मनी में काम के अनेक अवसर तो हैं, लेकिन भाषाई चुनौती भी है। इसको दूर करने के लिए हम मध्यप्रदेश लैंग्वेंज इंस्टीट्यूट खोलने की योजना बना रहे हैं, जिससे रोजगार के अवसरों के लिए भाषा चुनौती नहीं बनें और मध्यप्रदेश तथा जर्मनी के अधिकारियों के मध्य समन्वय के साथ भाषाई सहजता से काम हो सके। हमारे युवाओं को भाषा की समस्याओं का सामना न करना पड़े और वे जर्मनी में रोजगार की संभावनाओं का लाभ उठा सकें।

जर्मन उद्योगपतियों को मप्र आने का न्योता सीएम ने जर्मन उद्योगपतियों को मध्यप्रदेश में होने वाली आगामी वैश्विक समिट में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि हम दोनों देशों के अधिकारियों के बीच तकनीकी सहयोग में आने वाली बाधाओं को दूर करने का प्रयास करेंगे। जर्मनी और मध्यप्रदेश का आपसी सहयोग औद्योगिक क्रांति के नए द्वार खोलने में सहायक होगा। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में जर्मन एक्सपर्ट्स आएंगे, साथ ही टेक्नोलॉजी भी उपलब्ध कराएंगे। दोनों देश आपसी समन्वय से मध्यप्रदेश में औद्योगिक विकास के नए आयाम स्थापित करेंगे। उन्होंने कहा कि जर्मनी के टेक्नीकल स्टाफ के माध्यम से इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक, आईटीआई जैसे टेक्नीकल क्षेत्र में हमारे उद्योगपति लाभ ले सकेंगे। खासकर ऑटोमोबाइल क्षेत्र में जर्मन टेक्नोलॉजी उन्नत स्तर की है। उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि इसमें कई चुनौतियां भी सामने आएंगी।

जर्मनी को टेक्नोलॉजिकल फील्ड के वर्कर्स चाहिए सीएम ने कहा कि जर्मनी की आबादी बहुत थोड़ी सी है और इनमें भी ज्यादातर बुजुर्ग हो चुके हैं या फिर इस अवस्था को पहुंचने के करीब हैं। जर्मनी में टेक्नोलॉजिकल फील्ड में वर्कर्स की जरूरत है, हमारे यहां भी युवाओं को रोजगार की जरूरत है। दोनों एक-दूसरे पर निर्भर हैं, इसलिए भाषा की बाधा दूर करने के लिए हम एमपी में लैंग्वेज इंस्टीट्यूट खोलकर युवाओं को आगे बढ़ाएंगे। सीएम जर्मनी में उद्योगपतियों से एमपी में निवेश की संभावनाओं पर भी बात करेंगे। इसके पहले यूके में सीएम को एमपी के लिए 60 हजार करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिल चुके हैं। वे तीन दिन यूके के दौरे पर रहे, जो बुधवार को ही पूरा हुआ।

जर्मनी की टेक्नोलॉजी का लाभ लें भारतीय उद्योगपति सीएम ने कहा कि नई टेक्नोलॉजी के बल पर सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जिस ढंग से जर्मनी आर्थिक समृद्धशाली ताकत बनकर निकला है, यह दुनिया के सामने एक आदर्श उदाहरण है। जर्मनी की आबादी लगभग सवा आठ करोड़ है, लेकिन आज यह विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। सीएम ने कहा कि जर्मनी की टेक्नोलॉजी से हमारे यहां के उद्योगपति लाभ लें, खासकर ऑटोमोटिव सेक्टर में, इनके वाहन बहुत उन्नत प्रकार के हैं।

चौथी बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने हेमंत सोरेन, शपथ समारोह में पहुंचे मां-पिता

रांची। रांची के मोरहाबादी मैदान में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने रांची में झारखंड के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। हेमंत सोरेन चौथी बार राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं। हेमंत सोरेने के शपथ ग्रहण समारोह में उनके पिता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन और उनकी मां रूपी सोरेन भी मंच पर मौजूद रहीं। इस अवसर पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी मंच पर मौजूद थे। विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन ने भाजपा के गमलियाल हेम्ब्रोम को 39 हजार 791 मतों के अंतर से हराकर बरहेट सीट बरकरार रखी थी। जबकि झामुमो के नेतृत्व वाले गठबंधन ने 81 सदस्यीय झारखंड विधानसभा में 56 सीटें हासिल कर शानदार जीत हासिल की, जबकि भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए को 24 सीटें मिलीं। बता दें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने गठबंधन में सिर्फ 43 सीटों पर चुनाव लड़ा और 34 सीटें हासिल की थी। वहीं मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया पर कई पोस्ट किए हैं।

'बीजेपी के बाबा' बनाम 'कांग्रेस के बाबा': हिंदू जोड़ो पदयात्रा के बीच आ गई सियासत, भड़के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद

बीजेपी के नारे को लोगों तक पहुंचा रहे पं. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री

नई दिल्ली। छतरपुर के बाबा बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री इन दिनों हिंदू जोड़ो पदयात्रा पर निकले हैं। यह पदयात्रा ओरछा तक जाएगी। पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की इस यात्रा पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने बड़ी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को मोहरा बनाया गया है। अविमुक्तेश्वरानंद ने बागेश्वर बाबा की यात्रा को राजनीति से प्रेरित बताया है। उन्होंने कहा कि एक तरफ बीजेपी ने नारा दे रही है कि बंटोगे तो कटोगे। इसका मतलब जनता जातियों में न बंटकर एकमुश्त हमको वोट देती रहे। बीजेपी के नेताओं की भावना को जनता के बीच में ले जाने के लिए धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को मोहरा बनाया गया है। इसीलिए वे यात्रा में नारा लगा रहे हैं कि जात-पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। वे बीजेपी के नारे को लोगों तक पहुंचा रहे

हैं। उन्होंने कहा कि जात-पात में न बंटकर एकमुश्त वोट देने की बात कही जा रही है।

हिंदू की पहचान जाति से ही होती है शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि हिंदू की पहचान जाति से ही होती है। हिंदू में जाति ही पहचान होती है। अगर आपसे कोई पूछेगा आप कौन से हिंदू हो तो आप कहोगे कि हिंदू हैं तो आप पर कौन भरोसा करेगा। उन्होंने आगे कहा कि यह हमारी परंपरा है और हमारे यहां वर्णाश्रम का विचार है। अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि आंदोलन इसके लिए होना चाहिए कि वर्णाश्रम को मानते हुए किसी को नीचा दिखाने का काम नहीं करेंगे, लेकिन जात-पात की विदाई कर देंगे तो हमारी पहचान ही खत्म हो जाएगी। जब हमारी पहचान नष्ट हो जाएगी तो हम कैसे सनातनी रहेंगे। उन्होंने धीरेंद्र शास्त्री की यात्रा को राजनीतिक खेल बताया है।

कांग्रेस समर्थक होने के लगते रहे हैं आरोप अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर हमेशा से कांग्रेस समर्थक होने के आरोप लगते रहे हैं। करीब चार माह पहले स्वामी गोविंदाचार्य सरस्वती ने उन्हें फर्जी बाबा करार दिया था। उस वक्त वाराणसी कोर्ट का आदेश दिखाते हुए उन्होंने कहा था कि वाराणसी कोर्ट ने तो अविमुक्तेश्वरानंद को भगोड़ा घोषित किया था।

यूरेशियन ग्रुप की बैठक में वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी हुए शामिल

मनी लॉड्रिंग-आतंकवाद की फंडिंग पर कोई एक देश अंकुश नहीं लगा सकता

सिटी चीफ इंदौर।
इंदौर। यूरेशियन ग्रुप की बैठक में गुरुवार को मप्र के राज्यपाल मंगू भाई पटेल और केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी शामिल हुए। अपने संबोधन में राज्यपाल मंगू भाई ने कहा कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए मनी लॉन्ड्रिंग खतरा है। वहीं, केंद्रीय मंत्री चौधरी ने कहा कि आर्थिक बदलाव के इस दौर में मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के लिए होने वाली फंडिंग में तकनीक का इस्तेमाल होने लगा है। उन पर कोई एक देश रोक नहीं लगा सकता। इसके लिए विश्व के देशों के संगठित प्रयास जरूरी है। भारत लगातार इस दिशा में काम कर रहा है। डिजिटल ट्रांजेक्शन, यूपीआई का प्रचलन देश में तेजी से बढ़ा है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि धन शोधन और आतंकवाद को वित्त पोषण की रोकथाम के लिए यूरेशियन देशों का ग्रुप महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा की भारत सरकार टेरर फंडिंग के खिलाफ पूरी मजबूती के साथ कार्य कर रही है। भारत में काला धन अधिनियम,आर्थिक अपराध को रोकने के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं और ये लगातार जारी हैं। बैठक में केंद्रीय वित्त विभाग के अतिरिक्त सचिव विवेक अग्रवाल ने भी कार्यक्रम के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। इसके साथ ही कार्यक्रम में संभागायुक्त दीपक सिंह,कलेक्टर आशीष सिंह सहित तमाम जनप्रतिनिधि भी मौजूद थे।

राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग की जटिल समस्या को खत्म करने के लिए विश्व के देशों की अखंडता, एक समान नीतियां और समग्र प्रयास जरूरी है। भारत ने बीते कुछ वर्षों में आर्थिक बदलाव के साथ डिजिटल ट्रांजेक्शन को अपनाया है। इस सुविधा का गलत फायदा अपराधी भी उठाने लगे हैं। यूरेशियन समूह के सदस्य देशों ने एक साथ मिलकर इस पर मंथन किया है। इस मीटिंग के बेहतर निष्कर्ष निकलेंगे, जो देश की अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद होंगे। राज्यपाल ने कहा कि ईएजी ग्रुप देशों की यह बैठक मनी लॉन्ड्रिंग एवं आतंकवाद को फंडिंग रोकने में मील का पत्थर सिद्ध होगी। सभी बड़े देशों को एकजुट होकर मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग को रोकने के लिए एकजुट होकर बड़े कदम उठाने की आवश्यकता है। विश्व में आतंकवाद के पोषण पर नियंत्रण के लिए सभी ईएजी ग्रुप सदस्यों देशों का एकजुट होना बड़ा कदम है।

आतंकवाद सभी देशों के लिए खतरा
जलसंसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने कहा कि आतंकवाद सभी देशों के लिए खतरा रहते है। आतंकवादी घटना कही भी हो, लेकिन उसके लिए फंडिंग सीमा पार देशों से होती है। इस पर अंकुश लगाने के लिए एकीकृत प्रयास होना चाहिए। नए नियम और प्रावधान के जरिए इस तरह की गतिविधियों पर नजर रखी जा सकती है।

इसके लिए तकनीक भी मददगार साबित हो सकती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के प्रधानमंत्री कहा करते थे कि हम एक रुपया जनता के लिए भेजते हैं तो 25 पैसे ही पहुंचते हैं, लेकिन डिजिटल युग में मोदी सरकार ने केंद्र की राशि सीधे जरूरतमंद व पात्र लोगों के खाते में डालने का सिस्टम बनाया है। मीटिंग में अन्य विशेषज्ञों ने भी अपनी बात रखी। सभी अतिथियों के साथ राज्यपाल ने एक ग्रुप फोटो भी खिंचवाया।

एयर इंडिया एक्सप्रेस बैंकॉक फ्लाइट के साथ 2025 में देगी सौगात

इंदौर से सीधे कनाडा और अमेरिका जा सकेंगे हवाई यात्री

सिटी चीफ इंदौर।
इंदौर। इंदौर के देवी अहिल्याबाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए एक और बड़ी खुशखबरी सामने आई है। दरअसल एयरपोर्ट का विस्तार तेजी से हो रहा है। इसके चलते अब इंदौर से बैंकॉक के लिए भी सीधी इंटरनेशनल फ्लाइट मिल सकेगी। जानकारी के अनुसार यह फ्लाइट आने वाले साल यानी 2025 के शुरुआत में मिलना शुरू हो जाएगी। वहीं इस फ्लाइट का संचालन एयर इंडिया एक्सप्रेस द्वारा किया जाएगा। दरअसल बैंकॉक की फ्लाइट सीधे इंदौर से शुरू हो जाने से इंदौर से कनाडा और यूएस जाने वाले पैसेंजर को बड़ी राहत मिलेगी। वह आसानी से यूएस और कनाडा भी पहुंच सकेंगे। इंदौर से बैंकॉक जाने वाली एयरलाइंस की फ्लाइट कनाडा और यूएस से भी कनेक्ट की जाएगी। सूत्रों की माने तो इंदौर से बैंकॉक की चलने वाली फ्लाइट 2025 से शुरू हो जाएगी।

कंपनी को थाईलैंड के लिए मिली परमिशन
कंपनी को थाईलैंड के लिए परमिशन दे दी गई है। कंपनी द्वारा इंतजार किया जा रहा है सूरत-बैंकॉक फ्लाइट का। जैसे ही सूरत-बैंकॉक फ्लाइट चालू कर दी जाती है। वैसे ही इंदौर से बैंकॉक के लिए फ्लाइट मिलना शुरू हो जाएगी। जानकारी दे दें कि थाइलैंड में अराइवल विजा फ्री होता है। ऐसे में इंदौर से बैंकॉक जाने वाले यात्रियों के लिए यह राहत वाली खबर है। दरअसल इंदौर से बैंकॉक की फ्लाइट चल जाने से यूएस व कनाडा जाने वाले यात्रियों के लिए भी आसानी हो जाएगी। वे बैंकॉक की फ्लाइट लेकर बैंकॉक से फ्लाइट बदलकर यूएस और कनाडा जा सकेंगे।

ऑक्यूपेंसी को लेकर समस्या नहीं आएगी
ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़ चैप्टर के चेयरमैन हेमेंद्र सिंह जादौन के मुताबिक हम 2025 में इंदौर को बैंकॉक से जोड़ने जा रहे हैं। बैंकॉक फ्लाइट के साथ ही इंदौर को एक और इंटरनेशनल फ्लाइट मिलने की संभावना है। ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़ चैप्टर के पूर्व चेयरमैन टीके जोश के मुताबिक एयर इंडिया एक्सप्रेस के अधिकारी इंदौर आए थे। उन्होंने हमें बताया कि एयरलाइन की कोशिश है कि 2025 की शुरुआत में इंदौर-बैंकॉक फ्लाइट शुरू हो जाए।
उन्होंने बताया कि एयरलाइन ने इंदौर-बैंकॉक फ्लाइट के लिए सर्वे भी किया है। इसमें यह बात सामने आई है कि इस फ्लाइट के शुरू होने के बाद ऑक्यूपेंसी को लेकर समस्या नहीं आएगी।

इंडिगो भी बना रही इंदौर-बैंकॉक फ्लाइट का प्लान
एयर इंडिया एक्सप्रेस के साथ ही इंडिगो एयरलाइंस भी इंदौर से बैंकॉक के लिए डायरेक्ट फ्लाइट शुरू करने की प्लानिंग कर रही है। बैंकॉक फ्लाइट शुरू करने के लिए इंडिगो ने शहर के ट्रैवल एजेंट्स से चर्चा की है।
कंपनी इंदौर-बैंकॉक फ्लाइट के लिए सर्वे भी कर चुकी है। सूत्रों का कहना है कि इंडिगो को फ्लाइट शुरू करने में दिक्कत सिर्फ एयरक्राफ्ट की आ रही है। इंडिगो को नए एयरक्राफ्ट नहीं मिल पा रहे हैं। इंदौर से बैंकॉक और सिंगापुर के लिए सीधी फ्लाइट शुरू करने का प्रस्ताव सांसद शंकर लालवानी ने भी 11 महीने पहले एयरलाइंस कंपनी को भेजा था।

ताजपुर स्टेशन पर इलेक्ट्रानिक इंटरलाकिंग प्रणाली इंस्टॉल

यह प्रणाली अपनाने वाला देश का पहला स्टेशन

सिटी चीफ इंदौर।
इंदौर। रतलाम रेल मंडल का ताजपुर रेलवे स्टेशन इलेक्ट्रानिक इंटरलाकिंग प्रणाली लागू करने वाला देश का पहला स्टेशन बना है। इस प्रणाली का इस्तेमाल स्टेशनों पर ट्रेनों की सुरक्षित आवाजाही, सिग्नल, स्नीच, क्रासिंग गेट नियंत्रित करने के लिए हो सकेगा। इसके लिए स्टेशन पर 132 केवी का ट्रांसफार्मर भी लगाया गया है। भारतीय रेलवे अब ट्रेनों के संचालन के लिए आधुनिक तकनीक को भी अपना रहा है। रतलाम मंडल के ताजपुर रेलवे स्टेशन पर अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणाली को इंस्टॉल किया गया है। इस प्रकार की नई प्रणाली को इंस्टॉल करने वाला रतलाम मंडल भारतीय रेलवे में पहला स्टेशन बना है। इसके लिए रतलाम मंडल पर ओएचई(ओवर हेड इक्यूपमेंट) की क्षमता बढ़ाने के लिए नागदा-खाचरौद खंड में ट्रांसफार्मर स्थापित किया है। इसकी टेस्टिंग जारी है। इससे मालगाड़ियों की ढुलाई क्षमता बढ़ेगी। वोल्टेज (50 केवी) के दोगुना होने और बेहतर वोल्टेज मिलने से बिजली की खपत भी कम होगा। नए ट्रांसफार्मर की विद्युत सप्लाई से नई प्रणाली से निर्बाध ट्रेनों के संचालन में मदद मिलेगी और मानवीय गलतियों की संभावना काफी कम होगी। इलेक्ट्रानिक इंटरलाकिंग प्रणाली में तब तक ट्रेन को आगे बढ़ने का सिग्नल नहीं देता, तब तक कि लाइन साफ न हो।

युवा वकीलों को एक सप्ताह के भीतर अस्थायी सनद जारी करने के निर्देश

सिटी चीफ इंदौर।
इंदौर। मप्र के छह हजार से ज्यादा युवा वकीलों को मप्र हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने राज्य अधिवक्ता परिषद से कहा है कि वह एक सप्ताह के भीतर इन्हें अस्थायी सनद जारी कर दे। हाईकोर्ट ने यह आदेश हाईकोर्ट बार एसोसिएशन इंदौर के पूर्व सह सचिव राकेशसिंह भदौरिया द्वारा दायर याचिका का निराकरण करते हुए दिया है। याचिका में भदौरिया ने कहा था कि राज्य अधिवक्ता परिषद की नामांकन समिति की बैठक चार माह से अधिक समय से नहीं हुई है। इस वजह से कानून की पढ़ाई पूरी कर चुके युवा न्यायालयों में प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि नामांकन के अभाव में उन्हें अस्थायी सनद जारी नहीं हो पा रही है। प्रैक्टिस के अधिकार से वंचित होने के साथ ये युवा न्यायिक सेवाओं के लिए भी पात्रता हासिल नहीं कर पा रहे हैं। नामांकन समिति की अंतिम बैठक 29 जुलाई को हुई थी। इसके बाद से कोई बैठक नहीं हुई। एडवोकेट भदौरिया ने बताया राज्य अधिवक्ता परिषद ने याचिका में प्रस्तुत जवाब में कहा था कि अंकसूची का सत्यापन नहीं होने की वजह से आवेदकों को अस्थायी सनद जारी नहीं हो रही है। चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति विवेक जैन ने राज्य अधिवक्ता परिषद की ओर से प्रस्तुत तर्कों को दरकिनार करते हुए आदेश दिया कि सभी को एक सप्ताह के भीतर अस्थायी सनद जारी की जाए। उधर, इंदौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव 18 दिसंबर को होंगे। मुख्य चुनाव अधिकारी मनोज द्विवेदी ने बुधवार को चुनाव कार्यक्रम घोषित करते हुए मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन भी कर दिया। चुनाव के लिए 4 और 5 दिसंबर को नामांकन फार्म मिलेंगे। नामांकन फार्म की जांच 6 दिसंबर को होगी और इसी दिन वैध नामांकन पत्रों की सूची जारी कर दी जाएगी। नाम वापसी के लिए सिर्फ 9 दिसंबर का दिन दिया गया है। चुनाव समिति 10 दिसंबर को प्रत्याशियों की अंतिम सूची प्रकाशित कर देगी। 18 दिसंबर को सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। मतदान समाप्त होने के तुरंत बाद मतगणना शुरू हो जाएगी। देर रात तक परिणाम भी घोषित कर दिए जाएंगे। द्विवेदी ने बताया कि एसोसिएशन द्वारा उपलब्ध कराई गई आरंभिक मतदाता सूची में 2162 वैध नाम शामिल हैं। हमने सदस्यों से दावे-आपत्तियां बुलवाई हैं।

टेरेंस लुईस के स्टुडेंट पर लगा रेप का आरोप, लड़की को दिया शादी का झांसा

सिटी चीफ इंदौर।
इंदौर। इंदौर की राऊ थाना पुलिस ने डांस इंडिया डांस में हिस्सा ले चुके प्रतियोगी पर एक युवती की शिकायत के बाद हिंदू विवाह अधिनियम के उल्लंघन और दुष्कर्म का मामला दर्ज किया है। आरोपी मशहूर डांस कोरियोग्राफर टेरेंस लुईस का स्टूडेंट बताया जा रहा है। हाईकोर्ट के वकील कृष्ण कुमार कुन्हारे के मुताबिक आरोपी की युवती के साथ साल 2018 में जान पहचान हुई थी, उसने खुद को बॉलीवुड के मशहूर डांस कोरियोग्राफर टेरेंस लुईस का स्टूडेंट और डांस इंडिया डांस का प्रतियोगी बताया था। दोनों में प्यार का रिश्ता बन गया। आरोपी युवक ने युवती को शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। दोनों की एक संतान भी है। आरोपी पर युवती ने कई बार शादी का दबाव बनाया तो वह उसे कोर्ट ले गया और कोर्ट मैरिज कर ली। हालांकि, युवक हिन्दू रीति रिवाज से विधिवत शादी करने का झांसा देता रहा। वकील के मुताबिक कोर्ट के आदेश पर पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह ने राऊ थाने में मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए थे, जिस पर राऊ पुलिस ने दुष्कर्म और हिन्दू विवाह अधिनियम का उल्लंघन करने का मामला दर्ज कर लिया है। डीसीपी विनोद कुमार मीना के मुताबिक इंदौर की राऊ थाना पुलिस ने युवती की शिकायत पर युवक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस टीम बनाकर हरसंभव प्रयास कर रही है।

इंदौर आईं पीएम नरेंद्र मोदी की पत्नी जसोदा बेन, खजराना मंदिर में किए दर्शन

इंदौर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पत्नी जसोदा बेन इंदौर पहुंची। उनके साथ उनके भाई व अन्य परिजन भी आए थे। वे राजेंद्र नगर स्थित परिचित मनोज भागमल के निवास पर रुकीं। दोपहर में उन्होंने खजराना गणेश मंदिर में पूजा की। वर्ष 2017 में भी जसोदा बेन इंदौर आई थीं। तब वे नाथ मंदिर भी गई थीं। जसोदा बेन बुधवार रात साढ़े 11 बजे निजी वाहन से इंदौर पहुंची। भागमल परिवार ने उनका व साथ आए परिजनों का स्वागत किया। दोपहर में उनसे इंदौर में रहने वाले अन्य परिचित भी मिलने आए थे। इसके बाद वे खजराना मंदिर के लिए रवाना हुईं। वे मंदिर में करीब आधे घंटे रुकी। गर्भगृह में जाकर उन्होंने पूजा की। पुजारियों ने पूजा संपन्न कराने के साथ मंदिर समिति के कार्यों की जानकारी भी दी। गुजरात से जसोदा बेन अपने भाई और भतीजी के साथ इंदौर आई थीं। खजराना मंदिर में दर्शन करने के बाद वे देवास गईं। इसके बाद वे उज्जैन के लिए रवाना हो गईं। वहां से वे फिर गुजरात लौट जाएंगी।

कल आएंगे पं. धीरेंद्र शास्त्री, युवाओं को दिलाएंगे सनातन की रक्षा का संकल्प

सिटी चीफ इंदौर।
इंदौर। इंदौर में आयोजित होने जा रहे 5 दिवसीय सेवा मेले में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री 1 लाख युवाओं को सनातन की रक्षा का संकल्प दिलाएंगे। शहर के लालबाग परिसर में आयोजित मेला नारी शक्ति को समर्पित होगा। दरअसल, आज की वर्तमान पीढ़ी को भारत की पुरातन संस्कृति, संस्कार, सभ्यता और आध्यात्म से रूबरू कराने के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस मेले में बाबा बागेश्वर 'रग-रग हिन्दू मेरा परिचय' थीम पर युवाओं को प्रेरित करेंगे। मेले में मातृ-पितृ वंदन, कन्या पूजन, गुरू वंदन सहित अन्य नृत्य नाटकों की विशेष प्रस्तुतियां भी होंगी। हिंदू आध्यात्मिक एवं सेवा संस्थान इंदौर के चेयरमेन विनोद अग्रवाल ने बताया कि गुरुवार को शाम 4 बजे शस्त्र आराधना यात्रा दशहरा मैदान से निकाली गई। यह यात्रा विभिन्न मार्गों से होते हुए लालबाग पैलेस पहुंची, जहां इस यात्रा का समापन हुआ। हिंदुओं को जोड़ने के उद्देश्य से पं. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री 160 किलोमीटर लंबी सनातन हिंदू एकता पदयात्रा निकाल रहे हैं। यह पदयात्रा 21 नवंबर को बागेश्वर धाम से शुरू हुई थी और 29 नवंबर को ओरछा धाम में समाप्त होगी। 30 नवंबर को पं. धीरेंद्र शास्त्री इंदौर पहुंचेंगे।

युवाओं का मार्गदर्शन करेंगे धीरेंद्र शास्त्री
हिंदू आध्यात्मिक एवं सेवा संस्थान के अध्यक्ष राधेश्याम शर्मा ने बताया कि उद्घाटन समारोह की शुरुआत गुरुवार को शाम 6 बजे हुई। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पं. धीरेंद्र शास्त्री के व्याख्यान के लिए 2 लाख स्क्वायर फीट का हिस्सा तैयार किया जा रहा है। 30 नवंबर को पं. धीरेंद्र शास्त्री युवाओं का मार्गदर्शन करेंगे। हिन्दू युवा सम्मेलन पूरा हाईटेक होगा। इसके लिए पूरे परिसर में 10 से अधिक एलईडी स्क्रीन भी लगाई जाएंगी। खजराना गणेश मंदिर समिति की ओर से मेले में आने वाले भक्तों को निःशुल्क लड्डुओं का वितरण भी किया जाएगा।

आज स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह पहुंचेंगे
लालबाग में छोटा सा गांव भी बसाया गया है। ग्रामीण संस्कृति, परिवेश व खान-पान से भी यहां लोग रूबरू हो सकेंगे। वहीं खान-पान के शौकीनों के लिए यहां ग्रामीण परिवेश में बाजरा, मक्का, ज्वार, खिचड़ी सहित अन्य स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद भी चखने को मिलेगा। सेवा मेले के दूसरे दिन शुक्रवार को आचार्य वंदन कार्यक्रम प्रातः 10 बजे से आयोजित किया जाएगा। तेजी से घटती गुरु शिष्य परंपरा को एक बार फिर जीवंत करने के लिए 500 शिक्षकों का वंदन 1000 विद्यार्थियों के द्वारा किया जाएगा। मुख्य अतिथि के रूप में मध्यप्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह मौजूद रहेंगे। इस कार्यक्रम में जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी ज्ञानानंदजी तीर्थ महाराज भानपुरा पीठाधीश्वर सभा में शामिल होंगे।

आज से भोपाल में चार दिन का मजहबी समागम, सैकड़ों निकाह होंगे

सिटी चीफ भोपाल।

भोपाल। 77 साल पुरानी आलमी तबलीगी इज्तिमा की तहरीर एक बार फिर दोहराने के लिए तैयार है। शुक्रवार सुबह फजिर की नमाज के बाद होने वाले बयान के साथ इस चार दिवसीय समागम का आगाज हो जाएगा। दोपहर में यहां नमाज ए जुमा अदा होगी। शाम को असिर की नमाज के सादगी के साथ सैकड़ों निकाह होंगे। इस बीच देश दुनिया से आए उलेमाओं के तकरीर और बयान का सिलसिला भी जारी रहेगा। देशभर से आई हजारों जमाते अपनी आदम गुरवार रात से देना शुरू कर देंगी। विदेशों से आए मेहमान भी अपनी कागजी खानापूर्ति करने के बाद समागम का हिस्सा बन जाएंगे। मेहमानों की जरूरतों और सुविधा के लिहाज से इज्तिमागाह पर सारी तैयारियों चाक चौबंद कर दी गई हैं। आलमी तबलीगी इज्तिमा के दौरान शामिल होने वाले लाखों जमातियों में बुजुर्ग और बीमार भी होते हैं। इसके मद्देनजर किसी मेडिकल इमरजेंसी के लिए पहली बार बाइक एम्बुलेंस की व्यवस्था

की जा रही है। इज्तिमा मीडिया कोऑर्डिनेटर डॉ उमर हफीज ने बताया कि इज्तिमा पांडालों से दूर खड़ी रहने वाली एंबुलेंस तक पहुंचने में बीमारों को अक्सर परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस जरूरत के लिहाज से इस साल यह नई सुविधा शुरू की जा रही है। डॉ उमर ने बताया कि मोटर साइकिल के साथ एक स्ट्रेचर को अटैच करके खास तौर से यह बाइक एम्बुलेंस मोडिफाइड करवाई गई है। इसमें मरीज को लेटाने की सुविधा के साथ फर्स्ट एड बॉक्स की सुविधा भी जोड़ी है। जरूरत के लिहाज से इसमें ऑक्सीजन की व्यवस्था करने पर भी विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था से समय पर किसी मरीज को एंबुलेंस तक पहुंचाया जा सकेगा। जिससे उन्हें तत्काल अस्पताल तक पहुंचा कर मेडिकल सुविधा मुहैया कराई जा सके। उन्होंने बताया कि इसके अलावा इज्तिमगाह पर एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी आदि पद्धति के इलाज के लिए कई मेडिकल कैंप भी मौजूद रहेंगे।

प्रदेश सरकार का सकारात्मक रवैया

आलमी तबलीगी इज्तिमा के आयोजन को लेकर प्रदेश सरकार का हमेशा सकारात्मक रवैया रहा है। सड़क, पानी, बिजली समेत सुरक्षा आदि के प्रबंध में उच्च प्राथमिकता से यहां व्यवस्था दी जाती रही हैं। इसके अलावा 77 बरस के इस आयोजन में हर साल यहां आने वाले उलेमाओं से सरकार के शीर्ष नेताओं के मिलने और उनसे दुआएं लेने का रिवाज भी कायम रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने कार्यकाल में सबसे ज्यादा गंभीरता इस आयोजन को लेकर दिखाई है। वे हर साल उलेमाओं से मुलाकात के लिए भी पहुंचते थे और व्यवस्था पर भी उनकी गहरी रुचि और नजर रहा करती थी। वर्ष 2017 के इज्तिमा के दौरान ऐन एक दिन पहले इज्तिमा पहुंचने के लिए उनके लिए खासतौर से हेलीपैड भी बनाया गया था। लेकिन, इसके बाद अगले साल चुनावी आचार संहिता के चलते वे इस आयोजन में नहीं पहुंच पाए। फिर सरकार बदल और इसके बाद कोविड की वजह से किए गए इज्तिमा के छोटे आकार ने भी किसी मुख्यमंत्री को उलेमाओं तक जाने से रोक लिया। इसके बाद से लगातार अब तक कोई भी मुख्यमंत्री इज्तिमागाह नहीं पहुंचा है। इस साल भी मौजूदा मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव फिलहाल विदेश यात्रा पर लंदन में हैं। ऐसे में उनके भी उलेमाओं से मुलाकात के आसार कम ही नजर आ रहे हैं। हालांकि, तैयारियों के दौर में उन्होंने अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री कृष्णा गौर को जरूर इज्तिमागाह भेजा था। साथ ही व्यवस्थाओं के लिए प्रशासन को ताकीद कर रखी है।

बदल रही एक व्यवस्था

इज्तिमा में शामिल होने के लिए देशभर से बड़ी तादाद में जमाती पहुंचते हैं। इनमें आंध्र प्रदेश से बड़ी तादाद में आने वाले जमातियों के लिए एक स्पेशल ट्रेन भी आती रही है। कोविड के दौर में यह सिलसिला थम गया था। जिसके बाद से अब आंध्र प्रदेश से आने वाले जमाती अपनी निजी बसें लेकर यहां पहुंच रहे हैं। इज्तिमा का मजमा इकट्ठा होने से पहले पंडालों तक सामान पहुंचा देने वाली यह बसें पूरे समय पार्किंग में रहती हैं। दुआ ए खास होने और पूरा मजमा खाली होने के बाद इन बसों को यहां से निकाला जाता है।

एक पैगाम सादगी का

करीब 77 बरस के इज्तिमा के दौरान महंगी शादियों, दहेज जैसी बुराइयों और बड़ी दावतों पर बड़े खर्च को रोकने के लिए सादगी वाले निकाह भी इज्तिमा के दौरान होते हैं। शुरूआती दौर में कम संख्या के साथ शुरू हुआ निकाह का सिलसिला अब सैकड़ों में है। इस साल इज्तिमा में होने वाले निकाह की तादाद 350 से ज्यादा बताई जा रही है। इस लिहाज से अगर औसत निकाला जाए तो अब तक यहां 10 हजार से ज्यादा निकाह हो चुके हैं। लाखों लोगों की दुआओं के साथ होने वाले इस निकाह की कागजी खानापूर्ति लंबे अरसे तक शाहजहानाबाद हल्के के निकाहख्वाह काजी मुन्ने मियां अंजाम देते रहे हैं। उनके इंतकाल से कुछ समय पहले से उनके सहयोग के लिए हाफिज जुनैद अहमद भी जुड़ गए थे। आम दिनों में ली जाने वाली निकाह रजिस्ट्रेशन फीस में भी मसाजिद कमेटी कुछ रियायत देती है।

खूबसूरत प्रकृति, अमीर संस्कृति और विश्वस्तरीय पर्यटन स्थलों को प्रमोट किया एमपी ने

बेस्ट टूरिज्म स्टेट बना मध्यप्रदेश

सिटी चीफ भोपाल।

भोपाल। मध्यप्रदेश को देश का सबसे बेहतरीन पर्यटन राज्य चुना गया है। दिल्ली में हुए ट्रेवल एंड टूरिज्म कॉन्क्लेव एंड अवार्ड्स में मध्यप्रदेश पर्यटन विभाग को बेस्ट टूरिज्म स्टेट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला। यह पुरस्कार राज्य के पर्यटन के क्षेत्र में किए गए कामों और उनकी सफलता के लिए मिला है। राज्य की खूबसूरत प्रकृति, अमीर संस्कृति और विश्वस्तरीय पर्यटन स्थलों को प्रमोट करने के लिए पर्यटन विभाग नए-नए तरीके अपना रहा है। यह अवार्ड मध्यप्रदेश के पर्यटन के विकास में एक बड़ी उपलब्धि है। पर्यटन विभाग राज्य के पर्यटन स्थलों पर बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने, कनेक्टिविटी बढ़ाने और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए मौके पैदा करने पर काम कर रहा है। इन कोशिशों की वजह से मध्यप्रदेश देश-विदेश के पर्यटकों के लिए पसंदीदा जगह बनता जा रहा है। मध्यप्रदेश की प्राकृतिक सुंदरता पर्यटकों को अपनी ओर खींचती है। यहां घने जंगल, ऊंचे पहाड़ और झरने हैं। साथ ही, राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत भी देखने लायक है। ऐतिहासिक किले, मंदिर और खूबसूरत कलाकृतियां पर्यटकों को प्राचीन भारत की झलक दिखाती हैं।

राज्य में चल रहीं विभिन्न योजनाएं

राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। इनमें नए पर्यटन स्थलों का विकास, विज्ञापन और पर्यटकों के लिए बेहतर सुविधाएं शामिल हैं। पर्यटन विभाग डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी इस्तेमाल कर रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मध्यप्रदेश के पर्यटन स्थलों की जानकारी पहुंच सके।

ये हैं मध्यप्रदेश के मुख्य पर्यटन स्थल

मध्यप्रदेश में देश और प्रदेश के लोगों के लिए पसंदीदा हिल स्टेशन पचमढ़ी है, जहां हर साल लाखों पर्यटक आते हैं। इसे मध्यप्रदेश का श्रीनगर और स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। इसके बाद इंदौर का मांडू, यहां खूबसूरत पर्वतमालाओं के बीच 2 हजार फीट की उंचाई पर बसे मांडू में कभी परमार वंश का शासन था। यहां प्राकृतिक सुंदरता भरपूर है। खजुराहो में विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। यह शहर शिल्प और अंतराष्ट्रीय स्तर पर नृत्य समारोह के लिए भी आकर्षण का केंद्र है। इसी प्रकार मध्यप्रदेश में कई राष्ट्रीय वन्य जीव अभ्यारण्य और टाइगर रिजर्व हैं। महाकाल और अमरकंटक और चित्रकूट जैसे शहरों का धार्मिक महत्व है।

क्या बोले एमपी टूरिज्म बोर्ड के प्रमुख सचिव

मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड के प्रमुख सचिव श्री शिव शेखर शुक्ला ने इस पुरस्कार पर खुशी जताई। उन्होंने कहा, यह सम्मान प्रदेश में पर्यटकों को एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करने के लिये हमारे प्रयासों को और गति प्रदान करेगा। मध्यप्रदेश को पर्यटन की दृष्टि से और अधिक समृद्ध बनाने के लिए हम निरंतर प्रयासरत रहेंगे।

मध्यप्रदेश में अब कोर्ट में ऑनलाइन पहुंचेगी पुलिस केस डायरी

सिटी चीफ भोपाल।

भोपाल। मध्यप्रदेश में अब पुलिस केस डायरी कोर्ट में ऑनलाइन पहुंचेगी। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर पांच जिलों में इसे शुरू किया गया है। सफल रहा तो सभी जिलों में लागू होगा। पुलिस मुख्यालय का कहना है कि मध्य प्रदेश बेल एप्लीकेशन मैनेजमेंट सिस्टम बनाने वाला देश का पहला राज्य है। यह सिस्टम जमानत के आवेदनों को ऑनलाइन मैनेज करेगा। इससे समय और पैसा दोनों बचेगा। पुलिस मुख्यालय ने हाई कोर्ट के सुझाव पर इस सिस्टम का सॉफ्टवेयर तैयार करवाया है। इससे केस डायरी कोर्ट पहुंचने में होने वाली देरी कम होगी। पहले ई-समन लागू करने वाला भी मध्य प्रदेश पहला राज्य बना था। अब यह नया सिस्टम भी न्यायिक प्रक्रिया को और तेज और आसान बनाएगा। बेल एप्लीकेशन मैनेजमेंट सिस्टम अभी इंदौर, राजगढ़, देवास, सागर और भोपाल में शुरू हुआ है। पहले जमानत के लिए हाई कोर्ट, एसपी को पत्र लिखकर केस डायरी मांगता था। फिर एसपी थाने को सूचित करते थे। इसके बाद विवेचना अधिकारी डायरी तैयार करता था। इस पूरी प्रक्रिया में बहुत समय लगता था। नए सिस्टम से यह सब ऑनलाइन हो जाएगा। इससे आईओ का समय बचेगा, पुलिस का समय बचेगा और कोर्ट का समय भी बचेगा। मान लीजिए भोपाल में किसी पर केस दर्ज हुआ है। अब आरोपी जमानत के लिए हाई कोर्ट में आवेदन देता है। हाई कोर्ट अब सीधे ऑनलाइन सिस्टम के जरिए केस डायरी मंगा सकता है। आईओ डायरी ऑनलाइन अपलोड करेगा। इससे कागजी कार्रवाई और उसमें लगने वाला समय बचेगा। इससे पुलिसकर्मियों को बार-बार कोर्ट आना-जाना नहीं पड़ेगा। उनका कीमती समय बचेगा, जिसका इस्तेमाल वे दूसरे जरूरी कामों में कर सकेंगे। इस तकनीकी बदलाव से न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता भी बढ़ेगी। सभी जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध होगी, जिससे किसी भी तरह की गड़बड़ी की गुंजाइश कम होगी। आने वाले समय में अगर यह सिस्टम सफल रहता है, तो इसे पूरे मध्य प्रदेश में लागू किया जाएगा। इससे राज्य में न्याय व्यवस्था और मजबूत होगी।

बीजेपी ने मप्र संगठन चुनाव के लिए डॉ. सरोज पाण्डेय को पर्यवेक्षक बनाया

सिटी चीफ भोपाल।

भोपाल। बीजेपी ने मध्यप्रदेश में संगठन चुनाव के लिए डॉ. सरोज पाण्डेय को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। अगले महीने से डॉ. पाण्डेय मध्यप्रदेश के सभी संभागों में बैठकें लेंगी। ये बैठकें मंडल, जिला और प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के लिए होंगी। डॉ. पाण्डेय सभी सांसदों, विधायकों और संगठन पदाधिकारियों से वन टू वन बातचीत करेंगी। इसके बाद ही नियुक्तियां होंगी। डॉ. पाण्डेय भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। उन्हें यह जिम्मेदारी भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व ने दी है। उनके समर्थकों में खुशी की लहर है। मध्यप्रदेश के अलावा बीजेपी ने उन्हें तीन अन्य राज्यों की जिम्मेदारी दी है। बीजेपी के लिए ये संगठन चुनाव बेहद महत्वपूर्ण हैं। इन चुनावों के नतीजे पार्टी के भविष्य को प्रभावित करेंगे। डॉ. पाण्डेय अनुभवी नेता हैं। उन्हें संगठन का अच्छा अनुभव है। छत्तीसगढ़ की दिग्गज नेता सरोज का राजनीतिक सफर छात्र राजनीति से शुरू हुआ। उन्होंने पार्षद, विधायक और सांसद जैसे कई महत्वपूर्ण पद संभाले हैं। 2014 में लोकसभा चुनाव हारने के बाद भी वे सक्रिय रहीं। हाल ही में उनका राज्यसभा का कार्यकाल पूरा हुआ है। भिलाई में जन्मीं सरोज पांडे ने छात्र जीवन से ही राजनीति में कदम रखा। युवा सशक्तिकरण, शिक्षा और सामाजिक मुद्दों पर उनकी पैनी नजर रही है। उन्होंने दुर्ग जिले से एक ही साल में महापौर, विधायक और सांसद का पदभार संभाला। यह उपलब्धि हासिल करने वाली वह छत्तीसगढ़ की एकमात्र नेता हैं। साल 2000 में वे दुर्ग की महापौर बनीं। वे अपने गृहनगर में यह पद संभालने वाली पहली महिला थीं। लगातार दो कार्यकाल तक महापौर रहीं। खास बात यह है कि उन्हें लगातार दस साल तक सर्वश्रेष्ठ महापौर का पुरस्कार मिला। महापौर के रूप में मिली सफलता ने उनके राजनीतिक जीवन को नई ऊंचाइयां दीं। 2008 में उन्होंने वैशाली नगर विधानसभा चुनाव जीता। इसके बाद 2009 में उन्होंने दुर्ग लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और तीन बार के सांसद को हराकर जीत हासिल की। इस जीत ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। वे भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महासचिव और उपाध्यक्ष भी रह चुकी हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। मोदी लहर के बावजूद वे दुर्ग सीट से कांग्रेस उम्मीदवार ताम्रध्वज साहू से हार गईं। हालांकि, इस हार ने उनके हौसले नहीं तोड़े। वे राजनीति में सक्रिय रहीं और 2018 में छत्तीसगढ़ से भाजपा की पहली निर्वाचित राज्यसभा सांसद बनीं।

5 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज खुलेंगे

एमबीबीएस की 750 सीटें बढ़ेंगी

सिटी चीफ भोपाल।

भोपाल। मध्यप्रदेश में अगले शैक्षणिक सत्र से 5 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। ये कॉलेज बुधनी, मंडला, श्योपुर, सिंगरौली, राजगढ़ में खुलेंगे। इन सभी में 150-150 सीटें होंगी। इस तरह प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 750 सीटें बढ़ जाएंगी। वहीं, 12 नए प्राइवेट कॉलेज जिला अस्पतालों से संबद्धता के बाद खुलेंगे। इससे 1200 सीटें बढ़ेंगी, इस तरह कुल 1950 मेडिकल सीटें बढ़ने की संभावना है। इन कॉलेजों के शुरू होने के बाद प्रदेश में 21 सरकारी और 15 निजी कॉलेज हो जाएंगे, यानी इनकी कुल संख्या बढ़कर 36 हो जाएगी। इनके अलावा सरकार के इसी कार्यकाल में 12 नए प्राइवेट मेडिकल कॉलेज खुलना भी प्रस्तावित हैं। इनके बाद मध्यप्रदेश में कुल 48 मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि सरकारी और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़ाना हमारा लक्ष्य है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में भी मरीजों के लिए डॉक्टर आसानी से उपलब्ध हो सकेंगे। 12 जिलों में पीपीपी मोड पर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज भी खोले जा रहे हैं। प्रदेश में 2003 तक सिर्फ 5 सरकारी मेडिकल कॉलेज थे। बीते 20 वर्ष में 12 नए मेडिकल कॉलेज खुले और अब एक साथ 12 अन्य मेडिकल कॉलेज पीपीपी मोड पर शुरू किए जा रहे हैं। कटनी, टीकमगढ़, बालाघाट, धार, सीधी, खरगोन, पन्ना, बैतूल, भिंड, नर्मदापुरम, देवास और मुरैना में पीपीपी मोड पर मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। देशभर में सबसे ज्यादा 72 मेडिकल कॉलेज तमिलनाडु में हैं। दूसरे नंबर पर कर्नाटक में 70, तीसरे पर उत्तर प्रदेश में 68 मेडिकल कॉलेज हैं।

विजयपुर में जीत के बाद मप्र कांग्रेस का बूथ मैनेजमेंट पर फोकस

सिटी चीफ भोपाल।

भोपाल। मध्यप्रदेश में विजयपुर उपचुनाव में कांग्रेस की जीत और बुधनी में वोट प्रतिशत बढ़ने के बाद, पार्टी कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा देखी जा रही है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का बूथ मैनेजमेंट सफल माना जा रहा है। पटवारी का मानना है कि मध्य प्रदेश में जीत के लिए बूथ स्तर पर मजबूत होना जरूरी है। इसलिए अब कांग्रेस जमीनी कार्यकर्ताओं पर ध्यान केंद्रित करेगी। इसके लिए पार्टी के सभी पदाधिकारियों को हर महीने अपने काम का हिसाब देना होगा। इसमें दौरे, बैठकें और कार्यक्रम शामिल होंगे। काम के आधार पर ही आगे की जिम्मेदारी मिलेगी। लापरवाही बरतने वालों को हटाया जाएगा। हर तीन महीने में काम का मूल्यांकन भी होगा।

ब्लॉक स्तर से फीडबैक की तैयारी

कांग्रेस अब जिला और ब्लॉक स्तर से भी फीडबैक लेगी। इससे पदाधिकारियों के काम का सही आकलन हो सकेगा। जो अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरेगा उसे हटाया जा सकता है। हाल ही में जीतू पटवारी ने अपनी नई टीम घोषित की है। अब इन नेताओं को अपनी काबिलियत साबित करनी होगी। कांग्रेस ने पहले छोटी कार्यकारिणी बनाई थी। इसमें 17 उपाध्यक्ष और 71 महासचिव थे। विरोध के बाद 84 सचिव और 36 संयुक्त सचिव भी जोड़े गए। महासचिवों को जिलों का प्रभार दिया गया है। सचिव और सह-सचिव उनका सहयोग करेंगे।

सरकार को घेरने की करेंगे तैयारी

कांग्रेस संगठन को हर स्तर पर सक्रिय करना चाहती है। इसके लिए, जिलों में प्रशिक्षण शिविर लगाए जाएंगे। इन शिविरों में बूथ स्तर के कार्यकर्ता भी शामिल होंगे। प्रशिक्षण विभाग पार्टी की नीतियों और कार्यक्रमों की जानकारी देगा। साथ ही, बीजेपी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी किए जाएंगे। पार्टी का मानना है कि बीजेपी ने अपने वादे पूरे नहीं किए हैं।

हर महीने करना होगा दौरा

पार्टी के सभी पदाधिकारियों को हर महीने अपने प्रभार वाले जिले का दौरा करना होगा। उन्हें जिला और ब्लॉक के पदाधिकारियों के साथ बैठक करनी होगी। साथ ही पार्टी के कार्यक्रमों का नेतृत्व करना होगा और उसकी रिपोर्ट प्रदेश मुख्यालय को भेजनी होगी। इसके आधार पर हर तीन महीने में काम का मूल्यांकन किया जाएगा। जो पदाधिकारी काम में रुचि नहीं दिखाएंगे, उन्हें हटा दिया जाएगा। उनकी जगह युवा नेताओं को मौका दिया जाएगा। इसे लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि यह नया सिस्टम पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करेगा। पटवारी बूथ मैनेजमेंट को जीत की कुंजी मानते हैं। विजयपुर उपचुनाव की जीत से पार्टी का उत्साह बढ़ा है।

सम्पादकीय

'धर्मनिरपेक्षता' और 'समाजवाद' से पीछा छुड़ाने की प्रवृत्ति ठीक नहीं

सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि भारतीय अर्थ में समाजवादी होने का अर्थ केवल कल्याणकारी राज्य से है। संसद की संशोधन शक्ति प्रस्तावना तक भी फैली हुई है। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि प्रस्तावना को अपनाने की तारीख संसद की प्रस्तावना में संशोधन करने की शक्तिको सीमित नहीं करती है। इसी को आधार मानते हुए कोर्ट ने याचिकाकर्ता के तर्क को खारिज कर दिया। फैसले ने इस तथ्य की ओर फिर से ध्यान खींचा कि प्रस्तावना में सेकुलर शब्द जोड़े जाने से पहले भी संविधान का ढांचा सेकुलर ही था।

संविधान की प्रस्तावना से 'धर्मनिरपेक्ष' और 'समाजवादी' शब्द हटाने वाली याचिका को सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि भारतीय अर्थ में समाजवादी होने का अर्थ केवल कल्याणकारी राज्य से है। संसद की संशोधन शक्ति प्रस्तावना तक भी फैली हुई है। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि प्रस्तावना को अपनाने की तारीख संसद की प्रस्तावना में संशोधन करने की शक्तिको सीमित नहीं करती है। इसी को आधार मानते हुए कोर्ट ने याचिकाकर्ता के तर्क को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कहा कि जब इतने साल बीत गए फिर इस मामले को क्यों तूल देने की कोशिश की जा रही है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में इससे जुड़ी याचिकाएं पूर्व भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी, सामाजिक कार्यकर्ता बलराम सिंह और अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने दायर की थीं। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया था कि 42वें संशोधन ने संविधान निमार्ताओं की मूल दृष्टि को विकृत कर दिया। याचिकाकर्ताओं ने यह भी तर्क दिया था कि संविधान निर्माताओं ने संविधान सभा की बहसों के दौरान जानबूझकर समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को बाहर रखा था। याचिकाकर्ताओं ने साल 1976 की संसद की वैधता पर भी सवाल उठाया था। जो आपातकाल के दौरान और विस्तारित कार्यकाल के तहत संचालित हुई थी। सामाजिक कार्यकर्ता बलराम सिंह का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील विष्णु शंकर जैन ने तर्क दिया कि लोकसभा का कार्यकाल आपातकालीन आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए बढ़ाया गया था, न कि संविधान में संशोधन करने के लिए। सार्वजनिक परामर्श के बिना इन शब्दों को जोड़ने से संविधान निर्माताओं की मूल मंशा विकृत हो गई। वहीं, इस मामले में पूर्व भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने यह तर्क दिया कि इन शब्दों को शामिल करने से प्रस्तावना अपनी मूल स्वीकृति तिथि से असंगत हो गई है। उन्होंने इसी के साथ सुझाव दिया कि इन शब्दों को बाद में जोड़े गए शब्दों के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए, न कि यह माना जाना चाहिए कि वे मूल पाठ का हिस्सा थे। लेकिन संविधान की प्रस्तावना के इन दो शब्दों धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी को लेकर करीब आधी सदी से जारी बहस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से पूर्णविराम लगा दिया है। सर्वोच्च अदालत ने इससे जुड़ी याचिका को खारिज करते हुए दो बातें बिल्कुल साफ कर दीं। एक तो यह कि संविधान की प्रस्तावना में इन दो शब्दों को जोड़ना गलत नहीं था और दूसरी यह कि एक और संविधान संशोधन के जरिये इन शब्दों को प्रस्तावना से हटाने की कोई गुंजाइश नहीं रह गई है। इस क्रम में अदालत ने बहस के कई अहम पहलुओं पर रोशनी डाली, जिससे फैसले की सार्थकता और बहस की निरर्थकता दोनों स्पष्ट होती है। जैसा कि इस मामले में अदालत में दायर याचिका से भी स्पष्ट है, संविधान की प्रस्तावना में इन दो शब्दों को जोड़े जाने के लिए किए गए संशोधन को दो मुख्य आधारों पर गलत बताने की कोशिश की जाती रही थी। एक तो यह कि 1976 में यह संशोधन तब किया गया, जब लोकसभा का नियमित कार्यकाल समाप्त हो चुका था। दूसरी बात यह कि संविधान निर्माता इन दो शब्दों को जोड़े जाने के प्रस्ताव पर विचार करने के बाद उसे नामंजूर कर चुके थे। सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों आधारों को खारिज कर दिया। फैसले ने इस तथ्य की ओर फिर से ध्यान खींचा कि प्रस्तावना में सेकुलर शब्द जोड़े जाने से पहले भी संविधान का ढांचा सेकुलर ही था। समय-समय पर अलग-अलग मामलों में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से भी इस बात की तस्दीक होती रही है। जहां तक ये दो शब्द जोड़े जाने का सवाल है तो सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक देश की संसद को इस तरह के संशोधन करने का पूरा अधिकार है।

इंडस्ट्रीयल पार्क से ही बनेगा विकसित भारत...

भारत के विकास कार्यक्रमों में इंडस्ट्रीयल पार्क , स्मार्ट सिटीज और उनमें विकसित हो रहे छोटे और मध्यम दर्जे के उद्यमों का विशेष योगदान रहेगा, जैसे चीन में शेंजेन के स्पेशल इक्नॉमिक जोन और दूसरे औद्योगिक पार्कों का रहा है। इसी प्रकार अमेरिका में डेट्राइट में ऑटोमोबिल सेक्टर के विकास और सिलिकोन वेली में आईटी सेक्टर के उद्यमों के तेजी से विकास का योगदान रहा है। इसी प्रकार जर्मनी में इंजीनियरिंग उत्पादन के केंद्रों का देश के जीडीपी के विकास में बहुत योगदान रहा है ।

आज सारे विश्व में भारत के 7 प्रतिशत से अधिक दर से हो रहे सर्वाधिक तीव्र विकास की सराहना हो रही है, जिसके बारे में विश्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, एशियन विकास बैंक और सभी वैश्विक संस्थाओं ने प्रशंसात्मक टिप्पणी की है और माना है कि इस समय सारे विश्व के आर्थिक विकास के इंजन में सर्वाधिक योगदान भारत का है। इस सप्ताह जारी अंतरराष्ट्रीय संस्था मूडीज ने 'ग्लोबल मेको आउटलुक' रिपोर्ट में कहा है कि भारतीय इकोनॉमी 'स्वीट स्पॉट' जो 2024 में 7.2त्न की दर से बढ़ेगी। यह माना जा रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था 2025 तक, 4.34 ट्रिलियन डॉलर जीडीपी के साथ विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएगी, जो जापान के 4.31 ट्रिलियन डॉलर को पछाड़ देगी । इसका एक कारण यह है कि भारत में 2023 में जीडीपी के विकास की दर 7.8त्न रही जो जापान के 1.9त्न से कहीं अधिक है। इस गति से भारत की अर्थव्यवस्था 2047 तक 30 ट्रिलियन डॉलर पहुंचने की आशा है, जिसके फलस्वरूप भारत तब एक विकसित देश के रूप में उभरेगा।

इन सारे विकास कार्यक्रमों में देश में इंडस्ट्रीयल पार्क , स्मार्ट सिटीज और उनमें विकसित हो रहे छोटे और मध्यम दर्जे के उद्यमों का विशेष योगदान रहेगा, जैसे चीन में शेंजेन के स्पेशल इक्नॉमिक जोन और दूसरे औद्योगिक पार्कों का रहा है। इसी प्रकार अमेरिका में डेट्राइट में ऑटोमोबिल सेक्टर के विकास और सिलिकोन वेली में आईटी सेक्टर के उद्यमों के तेजी से विकास का योगदान रहा है। इसी प्रकार जर्मनी में इंजीनियरिंग उत्पादन के केंद्रों का देश के जीडीपी के विकास में बहुत योगदान रहा है । भारत की अर्थव्यवस्था छोटे और मध्यम दर्जों के उद्योगों (एमएसएमई) पर विशेष रूप से निर्भर है और आकंड़ों के मुताबिक देश की एक तिहाई जीडीपी उनसे आती है और लगभग 46त्न निर्यात भी इनके उत्पादनों पर आधारित है। रोजगार सृजन में भी एमएसएमई क्षेत्र का विशेष योगदान है जो जुलाई 2020 से जुलाई 2024 तक लगभग 21 करोड़ अनुमानित है।

औद्योगिक पार्कों और केंद्रों में, लॉजिस्टिक्स, वेयरहाउसिंग और ट्रांसपोर्टेशन के कारण समन्वित और समग्र विकास से, उत्पादन के लिए सप्लाई चेन की प्रभावी क्षमता में बहुत सुधार होता है और कीमतों में कमी होती है। इसके अलावा इन पार्कों में कुछ बड़े उद्योग जो इन केंद्रों में एन्कर उद्योगों का काम करते हैं इन अन्य उद्योगों को अनेक प्रकार से सर्पोट प्रदान करते हैं।

इन बड़े उद्योगो के विकास और आकर्षण के लिए भारत सरकार की अनेक योजनाएं, जैसे मेक इन इण्डिया, पीएलआई , पीएम गतिशक्ति इत्यादि कार्यरत हैं। कुल मिलाकर यह देश में उत्पादन बढ़ाने के लिए इंजन का काम करते हैं। इस समय भारत में केंद्र और राज्यों के सहयोग से अनेक औद्योगिक कॉरिडोर देश की अर्थव्यवस्था की धुरी बने हुए हैं और जीडीपी के विकास में पंख लगाने का काम कर रहे हैं। इनमें विशेष रूप से दिल्ली- मुंबई इंडस्ट्रीयल कॉरिडोर और चैनई इंडस्ट्रियल कोरिडोर उल्लेखनीय हैं।

इधर अनेक राज्यों में नए-नए कॉरिडोर और औद्योगिक केंद्र बन रहे हैं जो देश और क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास और रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और देशभर में मध्यम और छोटे शहरों के विकास में भी तेजी ला रहे हैं। इसी प्रकार यू.पी. में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर देश की रक्षात्मक जरूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जिसमें 6 केंद्र होंगे- अलीगढ़, आगरा, कानपुर, चित्रकूट, झांसी और लखनऊ। अगस्त 2024 में भारत सरकार ने एक महत्वाकांक्षी और युगांतरकारी पहल के अंतर्गत एनआईसीडीपी (राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम) की घोषणा की जिसमें देशभर में 28,600 करोड़ रुपये के निवेश से 11 राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकसित किए जाएंगे जिनमें बड़े-बड़े एंकर उद्योग और छोटे और मंझले दर्जे के एमएसएमईज विकसित होंगे और 2030 तक इनके द्वारा 2 ट्रिलियन डॉलर का निर्यात संभव हो पाएगा जो विकसित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इन 11 औद्योगिक कोरिडोर में दिल्ली- मुंबई के अतिरिक्त अमृतसर-कोलकता, बंगलुरु- मुम्बई, वाईजेक-चैनई, उड़ीसा, हैदराबाद - नागपुर, कोच्चि-कोइम्बटूर, देहली-नागपुर आदि सम्मिलित हैं। इनके अतिरिक्त एनआईसीडीपी परियोजना में कई नए औद्योगिक शहरों का, ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटीज के रूप में निर्माण किया जाएगा जिनमें उद्योग-धंधों के लिए प्लग एण्ड प्ले और वॉक टू वर्क जैसी सुविधाओं को विकसित किया जाएगा। इनमें गुजरात के धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रिजन (डीएसआईआर), महाराष्ट्र में औरंगाबाद इंडस्ट्रियल टाउनशिप, ग्रेटर नोएडा में इंटिग्रेटेड इंडस्ट्रीयल टाउनशिप और मध्यप्रदेश में इंटिग्रेटेड इंडस्ट्रीयल टाउनशिप, विक्रम उद्योगपुरी आदि शामिल हैं। केंद्र और राज्य सरकारों के अतिरिक्त प्राइवेट सेक्टर के अंतर्गत भी इन औद्योगिक केंद्रों के विकास में बहुत काम संभव है, और हो रहा है जो इनके समन्वित रूप से इनके विकास और एंकर डद्योगों की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, वेदान्ता ग्रुप ने घोषणा की है कि वे दो इंडस्ट्रीयल पार्क स्थापित करेंगे, जिनमें एक एल्यूमिनियम और दूसरा जिंक और चांदी के लिए होगा, जो तीनों धातुएं देश के इलेक्ट्रॉनिक्स और रिन्यूवेबल एनर्जी के जरूरतों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं इस परियोजना के लिए जो नो प्रोफिट नो लॉस पर आधारित होगी, राजस्थान और उडीसा में 1500 एकड़ में यह कल्स्टर स्थापित किए जाएंगे जिनसे एमएसएमईज और स्टार्ट-अप्स को डाउनस्ट्रीम की लिंकेज के आधार पर विकसित किया जाएगा । इनके अतिरिक्त अडानी ग्रुप ने भी इस संबंध में बहुत काम किया है।

औद्योगिक पार्कों के अतिरिक्त स्मार्ट सिटीज के द्वारा भी देश के समग्र और क्षेत्रीय विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान मिलने की आशा है इस संबंध में उद्योग मंत्री पियूष गोयल द्वारा जापान की विशाल कम्पनी टोयोटा द्वारा महाराष्ट्र के सांभाजीनगर में विकसित किये जा रहे एक महत्वपूर्ण औद्योगिक नगर का भी वर्णन किया गया था। वास्तव में आने वाले कुछ वर्षों में एनआईसीडीपी जैसी क्रान्तिकारी योजनाओं से देश के आर्थिक, औद्योगिक और क्षेत्रीय समन्वित विकास और रोजगार सृजन में तेजी से बढ़ावा देने में बहुत योगदान मिलेगा, जिनसे 2047 तक विकसित भारत के गंतव्य प्राप्ति में विशेष सहायता मिलेगी। बता दें कि भारत सरकार द्वारा देशभर में 10 इंडस्ट्रीयल स्मार्ट सिटी परियोजनाओं की शुरुआत की गई है, जिनमें से चार शहर पूरी तरह से विकसित हो चुके हैं। इनमें उज्जैन स्थित विक्रम उद्योगपुरी भी शामिल है, जहां 93 से अधिक उद्योगों ने भूमि प्राप्त कर ली है। यह स्मार्ट सिटी कुल 1133 एकड़ भूमि पर फैली हुई है और तेजी से विकास कर रही है। विक्रम उद्योगपुरी को दो हिस्सों में विकसित किया गया है। पहला हिस्सा विक्रम उद्योगपुरी है, जिसमें 467 एकड़ जमीन पर 57 उद्योग स्थापित किए गए हैं। इनमें से 10 यूनिट्स में उत्पादन शुरू हो चुका है, जबकि 15 से अधिक इकाइयों में निर्माण कार्य प्रगति पर है। इस क्षेत्र में कुल 6000 करोड़ रुपये का निवेश हो रहा है। दूसरा हिस्सा मेडिकल डिवाइस पार्क है, जहां 100 एकड़ जमीन पर 36 उद्योग लगाए जा रहे हैं। यहां सभी उद्योगों के लिए भूमि पहले ही आवंटित हो चुकी है। अब यहां जगह ही नहीं बची है। आगे की जरूरतों को पूरा करने के लिए नए इंडस्ट्रियल एरिया का प्रस्ताव रखा गया है। इसके तहत 7 गांवों की 1280 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। उज्जैन के अलावा, देश में अन्य प्रमुख इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी परियोजनाओं पर भी काम तेजी से जारी है। धोलेरा (गुजरात), औरिक (महाराष्ट्र) और कृष्णापट्टनम (आंध्र प्रदेश) में ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा चुका है। इसके साथ ही तुमकुरु (कर्नाटक), नांगल चौधरी (हरियाणा), और दादरी, ग्रेटर नोएडा (उत्तर प्रदेश) में भी बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जा रहा है।

अजमेर दरगाह शरीफ की चर्चा के बीच... ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती

ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती फारसी मूल के सुन्नी मुस्लिम दार्शनिक और धार्मिक विद्वान थे। उन्हें गरीब नवाज और सुल्तान-हिंद के नाम से भी जाना जाता था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 13वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप में आए और राजस्थान के अजमेर में बस गए। उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप में सुन्नी इस्लाम के चिश्ती आदेश की स्थापना की और उसका प्रसार किया। यह एक रहस्यमय सूफी सिलसिला था। उनकी खानकाह अजमेर में है, जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह है। इस दरगाह की वास्तुकला इंडो-इस्लामिक है। दरअसल, अजमेर दरगाह इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। यूपी के संभल में स्थित जामा मस्जिद के बाद अब राजस्थान के अजमेर में दरगाह शरीफ का सर्वे हो सकता है। एक निचली अदालत ने हिंदू पक्ष की उस याचिका को स्वीकार कर लिया है, जिसमें अजमेर शरीफ दरगाह को हिंदू मंदिर बताया गया है। इसमें कहा गया है कि यहां पहले एक शिव मंदिर था। याचिका हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की ओर से दायर की गई थी। जानते हैं ख्वाजा की पूरी कहानी।

'सूफी' शब्द अरबी के 'सफ' शब्द से लिया गया है जिसका मतलब है-ऊन से बने कपड़े पहनने वाला। इसका एक कारण यह है कि ऊनी कपड़ों को आमतौर पर फकीरों से जोड़कर देखा जाता था। इस शब्द का एक अन्य संभावित मूल 'सफा' है जिसका अरबी में अर्थ 'शुद्धता' भी है। वैसे भी अरब के लोग रेत भरी आंधी से बचने के लिए ऊनी कपड़े पहनते थे। सूफी सुलह-ए-कुल यानी शांति और सद्भावना में यकीन रखते हैं। उनके यहां की पीरी-मुर्शीदी की परंपरा भारत के गुरु-शिष्य परंपरा की तरह ही है। यह इस्लामी रहस्यवाद का एक रूप है जो वैराग्य पर जोर देता है। इसमें ईश्वर के प्रति समर्पण और भौतिकता से दूर रहने पर बल दिया गया है। सूफीवाद में बोध की भावना से ईश्वर की प्राप्ति के लिए आत्म अनुशासन को एक आवश्यक शर्त माना जाता है। रूढ़िवादी मुसलमानों के विपरीत जो कि बाहरी आचरण पर जोर देते हैं, सूफियों ने आंतरिक शुद्धता पर जोर दिया। सूफी मानते हैं कि मानवता की सेवा करना ईश्वर की सेवा के समान है। इतिहासकार डॉ. दानपाल सिंह के अनुसार, भारत में इस्लाम जब आया तो तलवारों से लैस मुस्लिम आक्रमणकारियों के साथ आया। ऐसे में इसे सहजता से स्वीकार करने में हिंदुस्तान की जनता को काफी मुश्किल हुई। इल्तुतमिश, बलबन और अलाउद्दीन खिलजी जैसे सुल्तानों ने जबरन धर्मांतरण की काफी कोशिश की, मगर ऐसा हो नहीं पाया। ऐसे में इस्लाम के हृदय के रूप में सूफी का जन्म हुआ, जो संगीत और नृत्य की बदौलत काफी कुछ भक्ति मार्ग से मिलता-जुलता था। ऐसे में तब जाकर हिंद-इस्लामी संस्कृति विकसित हुई। अमेरिकी विद्वान जॉन एस्पोसिटो के अनुसार, वह पहले प्रमुख इस्लामी रहस्यवादियों में से एक थे जिन्होंने औपचारिक रूप से अपने अनुयायियों को उनकी भक्ति, प्रार्थनाओं और भगवान के भजनों में संगीत के इस्तेमाल को शामिल करने की अनुमति दी थी। अरब आस्था उन स्वदेशी लोगों से अधिक संबंधित है जिन्होंने हाल ही में इस धर्म में प्रवेश किया है। वैसे तो सूफी परंपरा या सिलसिले कई तरह के थे। मगर, भारत में 4 तरह के सिलसिले ज्यादा प्रचलित थे। ये थे-चिश्ती, सुहरावर्दी, नक्शबंदी और कादरी सिलसिले। इनमें भी चिश्ती और सुहरावर्दी सिलसिले ज्यादा पॉपुलर हुआ करते थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती इसी चिश्तिया सिलसिले से थे। सफी लोग खानकाहों यानी एक तरह के आश्रम में रहते हैं, जहां उनके अनुयायियों का जमावड़ा रहता है। यहां संगीत यानी समां का आयोजन होता है, जिसमें कव्वाली पर झूम-झूमकर लोग ईश्वर से नाता जोड़ने की कोशिश करते हैं।

ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने वर्ष 1192 ई. में अजमेर में रहने के साथ ही उस समय उपदेश देना शुरू किया, जब मुहम्मद गोरी (मुईजुद्दीन मुहम्मद बिन साम) ने तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराकर दिल्ली में अपना शासन कायम कर लिया था। आध्यात्मिक ज्ञान से भरपूर चिश्ती के शिक्षाप्रद प्रवचनों ने जल्द ही स्थानीय आबादी के साथ-साथ सुदूर इलाकों में राजाओं, रईसों, किसानों और गरीबों को आकर्षित किया। उनकी मृत्यु के बाद मुगल बादशाह हुमायूं ने वहां पर उनकी कब्र बनवा दी। अजमेर में उनकी दरगाह पर मुहम्मद बिन तुगलक, शेरशाह सूरी, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, दारा शिकोह और औरंगजेब जैसे शासकों ने जियारत की। भारत में चिश्ती सिलसिले की स्थापना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी। इस सिलसिले में ईश्वर के साथ एकात्मकता (वहदत अल-वुजुद) के सिद्धांत पर जोर दिया जाता है। इस सिलसिले के सदस्य शांतिप्रियता में यकीन रखते थे। उन्होंने सभी भौतिक वस्तुओं को ईश्वर के चिंतन से भटकाव की वजह बताकर खारिज कर दी थी। खुद मोइनुद्दीन चिश्ती ने मोहम्मद गोरी से किसी तरह का तोहफे लेने से मना कर दिया था।

चिश्ती सिलसिले ने ईश्वर के नाम को जोर से बोलकर और मौन रहकर जपने यानी धिक्र जाहरी और धिक्र खाफी पर जोर दिया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्यों जैसे-ख्वाजा कुतबुद्दीन बख्तियार काकी, फरीदउद्दीन गंज-ए-शकर, निजामुद्दीन औलिया और नसीरुद्दीन चिराग वगैरह ने चिश्ती की शिक्षाओं को लोकप्रिय बनाने में अहम भूमिका निभाई। शेख बहाउद्दीन जकारिया ने सूफीवाद के सुहरावर्दी संप्रदाय की स्थापना की थी। भारत में शेख शहाबुद्दीन सुहरावार्दी मकतूल ने इस सिलसिले को कायम किया था। चिश्ती सिलसिले के विपरीत सुहरावर्दी सिलसिले को मानने वालों ने सुल्तानों, राज्य के संरक्षण और अनुदान को स्वीकार किया। शेख शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी और हमीदुद्दीन नागोरी इस संप्रदाय के अन्य लोकप्रिय संत थे। ये सिलसिला मुख्य रूप से पंजाब और सिंध के इलाके में ज्यादा पॉपुलर हुआ। नक्शबंदी सिलसिले की स्थापना ख्वाजा बहा-उल-दीन नक्शबंद ने की थी। भारत में इस सिलसिले की स्थापना ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी ने की थी। शुरूआत से ही इस सिलसिले के फकीरों ने शरियत के पालन पर जोर दिया। इस सिलसिले ने इस्लाम के प्रसार में ज्यादा अहम भूमिका निभाई। कादिरिया सिलसिला पंजाब में लोकप्रिय था। इसकी स्थापना बगदाद के शेख अब्दुल कादिर गिलानी ने 14वीं शताब्दी में की थी। इस सिलसिले के अनुयायी मुगल बादशाह अकबर के शासन के पक्के समर्थक थे। मियां मीर भी पॉपुलर सूफी संत थे। यह संप्रदाय अरबी बोलने वाले देशों के साथ-साथ तुर्की, इंडोनेशिया, अफगानिस्तान, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान जैसे कई देशों में पॉपुलर है।

ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती एक सूफी फकीर संत और दार्शनिक थे। उनका जन्म 1143 ई. में ईरान के सिस्तान क्षेत्र में हुआ था। यह वर्तमान में ईरान के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है, जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा से लगा हुआ है। चिश्ती ने अपने पिता के कारोबार को छोड़कर आध्यात्मिक जीवन को अपनाया। अपनी आध्यात्मिक यात्रा के दौरान उनकी मुलाकात प्रसिद्ध संत हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी से हुई। उन्होंने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को अपना शिष्य स्वीकार किया और उन्हें दीक्षा दी। 52 साल की उम्र में उन्हें शेख उस्मान से खिलाफत मिली। इसके बाद वे हज, मक्का और मदीना गए। वहां से वह मुल्तान होते हुए वह भारत आए और अजमेर में अपना ठिकाना बनाया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की मृत्यु 1236 ई. में हुई। उन्हें अजमेर में दफनाया गया। उनकी कब्र (दरगाह) ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर शरीफ दरगाह के नाम से प्रसिद्ध है। यह उनके अनुयायियों के लिए बेहद पवित्र स्थान है। इल्तुतमिश, अकबर, रजिया सुल्तान, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब जैसे बादशाहों ने यहां आकर जियारत की थी। बड़ौदा के महाराजा ने दरगाह शरीफ के ऊपर एक सुंदर आवरण बनवाया था। मुगल बादशाह जहांगीर, शाहजहां और जहांआरा ने इसके जीर्णोद्धार में योगदान दिया। हर साल ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की पुण्यतिथि को उर्स नामक त्योहार मनाया जाता है। खास बात यह है कि मृत्यु की सालगिरह पर शोक मनाने की बजाय जश्न मनाया जाता है। ऐसा इसलिए है, क्योंकि अनुयायियों का मानना है कि इस दिन मुर्शीद यानी शिष्य अपने ऊपर वाले यानी ईश्वर से फिर मिल जाता है। बता दें कि सूफी इस्लाम को मानने वाले राजस्थान की अजमेर शरीफ दरगाह को सबसे पवित्र तीर्थस्थलों में से एक मानते हैं ।यहां मुस्लिम संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की मजार है, जहां हर धर्म के लोग जियारत और अकीदत पेश करने आते हैं।

यहां हमअजमेर पर लिखी गई एक किताब का जिक्र कर रहे हैं, जो यहां के हिस्टोरिकल फैक्ट को बताती है। इसके चैप्टर 8 के पेज 82 से 89 तक अजमेर की ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह का इतिहास बताया गया है। इसी पुस्तक में दरगाह की जगह एक मंदिर होने की बात कही गई है। इस मंदिर में पूजा अर्चना किए जाने की भी बात लिखी गई है। यह किताब हिंदू सेवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की ओर से न्यायाधीश मनमोहन चंदेल के समक्ष पेश की गई है। दरअसल, किताब में इस बात का जिक्र है कि यहां ब्राह्मण दंपती रहते थे। वे दरगाह स्थल पर बने महादेव मंदिर में पूजा-अर्चना करते थे। इसके अलावा कई अन्य तथ्य हैं, जो साबित करते हैं कि दरगाह से पहले यहां शिव मंदिर रहा था। दरअसल, इस किताब के लेखक का नाम हरबिलास शारदा है। हरबिलास शारदा कोई आम व्यक्ति नहीं थे। वो जोधपुर हाईकोर्ट में सीनियर जज के रूप में रहे हैं। इन्होंने अपनी सेवा अजमेर मेरवाड़ा (1892) के न्यायिक विभाग में भी रहकर दी है। बड़ी बात यह है कि अजमेर में उनके नाम से हरबिलास शारदा मार्ग भी है। इन्होंने ही 1911 में इस किताब को लिखा था।

याचिकाकर्ता के वकील रामस्वरूप बिश्नोई ने सेवानिवृत्त न्यायाधीश हरविलास शारदा की पुस्तक का हवाला दिया, जिसमें बताया गया है कि दरगाह के निर्माण में हिंदू मंदिर के मलबे का इस्तेमाल किया गया था। पुस्तक में दरगाह के भीतर एक तहखाने का विवरण दिया गया है, जिसमें कथित तौर पर एक शिव लिंग होने का दावा है। पुस्तक में दरगाह की संरचना में जैन मंदिर के अवशेषों का भी उल्लेख किया गया है और इसके 75 फीट ऊंचे बुलंद दरवाजे के निर्माण में मंदिर के मलबे के तत्वों का भी इसमें वर्णन है। कहा गया है कि इस शिवलिंग की पारंपरिक रूप से एक ब्राह्मण परिवार पूजा करता है, और दरगाह के 75 फीट ऊंचे बुलंद दरवाजे की संरचना में जैन मंदिर के अवशेषों की उपस्थिति का संकेत देता हैष याचिका में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से दरगाह का सर्वेक्षण करने का भी अनुरोध किया, जिसमें उस क्षेत्र में फिर से पूजा-अर्चना की जा सके जहां शिव लिंग बताया जाता है। अजमेर के बारे में रोचक तथ्य यह भी है कि यहां पृथ्वीराज चौहान ने भी शासन किया था। जज हरविलास की किताब में बताया गया है कि अजमेर महायोद्धा पृथ्वीराज चौहान के वंशजो ने ही यह मंदिर बनाया था।

पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक नशा तस्कर को किया गिरफ्तार

338 ग्राम से अधिक स्मैक हुई बरामद

गौरव सिंघल । सिटी चीफ

सहारनपुर । देवबंद, देवबंद कोतवाली पुलिस ने चैकिंग के दौरान नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है। जिसके पास से पुलिस ने 338 ग्राम से अधिक स्मैक बरामद की है। जिसकी अंतर्राष्टीय बाजार में 50 लाख रुपये की कीमत बताई जा रही है।एसपी देहात सागर जैन ने बताया कि देवबंद कोतवाली पुलिस देवबंद-बंहेडा मार्ग पर चैकिंग कर रही थी। इस दौरान देवबंद की ओर से आ रहे बाइक सवार को रोककर पूछताछ की तो उसकी बातें संदिग्ध लगने पर उसकी चैकिंग की गई। चैकिंग के दौरान उसके पास से 338.34 ग्राम अवैध स्मैक बरामद की गई। गिरफ्तार किया गया आरोपी जनपद के नकुड थाना क्षेत्र के गांव घाटमपुर का निवासी साजिद पुत्र अफलातून है। सागर जैन ने बताया कि पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह उक्त स्मैक गंगोह थाना क्षेत्र के गुज्जरवाड़ा से लेकर आ रहा था। जिसे स्पलाई करने के लिए उत्तराखंड के झबरेडा की ओर जा रहा था। उनके मुताबिक साजिद पहले भी नशे की तस्करी समेत विभिन्न आरोपो में जेल जा चुका है। देवबंद कोतवाली प्रभारी सुनील नागर ने बताया कि अभियुक्त के कब्जे से 338.34 ग्राम स्मैक (अन्तर्राष्टीय अनुमानिक कीमत 50 लाख रूपये) व घटना में प्रयुक्त एक मोटर साइकिल बरामद की गई है। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध थाना देवबंद पर मु0अ0स0 653/24 धारा 8/21/29/60 NDPS ACT पंजीकृत किया गया। अभियुक्त पूर्व में भी जनपद के अलग-अलग थानों से जेल जा चुका है। अभियुक्त के आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

रिश्वत लेते रंगेहाथ पकड़े गए ग्राम पंचायत सचिव सुब्रा सोनी

होम लोन एनओसी के लिए रिश्वत मांगने पर पंचायत सचिव गिरफ्तार

कटनी, कटनी जिले के खड़ौला ग्राम पंचायत सचिव सुब्रा सोनी को जबलपुर लोकायुक्त की टीम ने 10 हज़ार रुपए की रिश्वत लेते रंगेहाथ अरेस्ट कर कार्यवाही की जा रही है। जबलपुर लोकायुक्त डीएसपी नीतू त्रिपाठी ने बताया कि खड़ौला ग्राम पंचायत सचिव सुब्रा सोनी ने शिकायतकर्ता बल्लू यादव से होम लोन लेने के लिए एनओसी देने के नाम पर 30 हज़ार रुपए रिश्वत के रूप में मांग की थी और जब यह बात 21 हज़ार रुपए में डन हो गई तो शिकायतकर्ता ने जबलपुर लोकायुक्त में इसकी शिकायत की जिसके साक्ष्य इक्कठा कर खड़ौला ग्राम पंचायत सचिव सुब्रा सोनी को शिकायतकर्ता के हाथ रिश्वत की पहली किस्त 10 हज़ार रुपए लेते रंगेहाथ अरेस्ट कर कार्यवाही की जा रही है।

बाल विवाह के रोकथाम के प्रति जनजागरूकता पर आधारित वेबीनार का हुआ आयोजन

वर्चुअल माध्यम से केन्द्रीय महिला बाल विकास मंत्री ने बाल विवाह मुक्त भारत बनाने दिलाई प्रतिज्ञा

सुशिल सोनी । सिटी चीफ

अनूपपुर, बाल विवाह की रोकथाम के प्रति जनजागरूकता लाने बाल विवाह मुक्त भारत अभियान का वर्चुअल माध्यम से शुभारम्भ महिला बाल विकास विभाग की केन्द्रीय मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी द्वारा विज्ञान भवन नई दिल्ली से वर्चुअल माध्यम से किया गया। इस कार्यक्रम में भारत सरकार के द्वारा एक पोर्टल लांच किया गया एवं बाल विवाह मुक्त भारत बनाने हेतु सामूहिक प्रतिज्ञा भी ली गई। वर्चुअल कार्यक्रम को देखने एवं सुनने के लिए कलेक्ट्रेट स्थित सोन सभागार में आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई थीं। कार्यक्रम में महिला बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी, परियोजना अधिकारी, पर्यवेक्षक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, जिले के सभी थानों से बाल कल्याण अधिकारी, स्वयं सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि, धर्मगुरु, सेवा प्रदाता आदि उपस्थित हुए। जेण्डर आधारित हिंसा के रोकथाम हेतु 25 नवम्बर से 10 दिसम्बर 2024 तक आयोजित किए जा रहे जनजागरूकता अभियान ''हम होंगे कामयाब'' पखवाड़ा के तहत यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बाल विवाह रोकथाम के लिए बाल विवाह निषेध अधिनियम और इन कानूनों के उल्लंघन के कानूनी परिणामों पर वेबीनार और सत्र का आयोजन किया गया। महिला बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी ने बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि इस कानून का मकसद समाज में बाल विवाह को रोकना है। इस कानून के तहत 18 साल से कम उम्र की महिला तथा 21 साल से कम उम्र के पुरुष के विवाह को बाल विवाह माना जाता है। बाल विवाह को दण्डनीय अपराध माना गया है। बाल विवाह करने वाले वयस्क पुरुष या बाल विवाह सम्पन्न कराने वालों को दो साल तक जेल या एक लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनो हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि वर्ष 2017 में इस कानून में संशोधन करते हुए बाल विवाह में भागीदार सभी सेवा प्रदाताओं को इसके दायरे में लाया गया है। टेन्ट, कैटरिंग, बैण्ड बाजे, डीजे, कार्ड प्रिन्टर, विवाह कराने वाले आदि या विवाह में किसी भी प्रकार की सेवा प्रदाय करने वाले सभी सेवा प्रदाताओं को इसके दायरे में लाया गया है। यदि यह सेवा प्रदाता बाल विवाह में सम्मिलित होते हैं, तो उन्हें भी सजा का प्रावधान है।

रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव सम्बन्धी कमिश्नर ने ली बैठक

मोहम्मद मुनीर । सिटी चीफ

शहडोल । कमिश्नर शहडोल संभाग श्रीमती सुरभि गुप्ता ने आज कमिश्नर कार्यालय शहडोल के अमरकंटक सभाकक्ष में, जनवरी 2025 में आयोजित होने वाली रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव के संबंध में बैठक ली। बैठक में कमिश्नर श्रीमती सुरभि गुप्ता ने शहडोल संभाग के इन्वेस्टरों की सूची तैयार करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होने कहा कि शहडोल संभाग में औद्योगिक विकास एवं रोजगार की अपार संभावना है। शहडोल संभाग में प्राकृतिक संसाधनों की कोई कमी नहीं हैं, यहां खनिज, वन संपदा, कृषि, उद्यानिकी, डेयरी, आयुर्वेदिक उत्पादों की अच्छी संभावनाएं है। इस हेतु शहडोल संभाग के उद्यमियों एवं इन्वेस्टरों की सूची तैयार कर उन्हें ज्यादा से ज्यादा संख्या में रीजनल इंडस्ट्रीअल कॉन्क्लेव में आमंत्रित करने हेतु कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए।

बैठक में कलेक्टर शहडोल डॉ केदार सिंह, पुलिस अधीक्षक शहडोल राम जी श्रीवास्तव, अपर कलेक्टर उमरिया शिवगोविंद सिंह मरकाम, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सोहागपुर अरविंद शाह, कार्यकारी संचालक एमपीआईडीसी श्री यू.के तिवारी, सहित कृषि विभाग, खनिज विभाग, उद्यानिकी, सहित अन्य विभागीय अधिकारी एवं विभिन्न उद्योगों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

मंडलायुक्त की अध्यक्षता में सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक संपन्न

प्राधिकरण की बैठक में लिए गए विभिन्न निर्णय

गौरव सिंघल । सिटी चीफ

सहारनपुर, मंडलायुक्त डॉ0 हृषिकेश भास्कर यशोद की अध्यक्षता में सर्किट हाउस सभागार में सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण सहारनपुर की बैठक आहूत की गई। बैठक में एजेण्डा बिन्दु के अनुसार विभिन्न मदों पर विस्तार से चर्चा की गई, तदोपरान्त महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये। मोटरगाडी अधिनियम 1988 की धारा-82(1) के अन्तर्गत 04 प्रार्थना पत्रों पर विचार करते हुए परमिटों को हस्तान्तरण की स्वीकृति दी गयी। मोटर गाडी अधिनियम 1988 की धारा-82(3) के अन्तर्गत परमिट धारक की मृत्यु के उपरान्त उनके वारिसानों से प्राप्त 01 प्रार्थना पत्रों पर विचार करते हुए स्वीकृति दी गयी है। परमिट पर वाहन पृष्ठांकन के लिए प्राप्त 01 प्रार्थना पत्र पर विचार करते हुए स्वीकृति प्रदान की गयी। अशोक कुमार पुत्र रघुवीर सिंह निवासी बुढाना जिला मुजफ्फरनगर का परमिट संख्या- पीएसटीपी-450 मार्ग शाहपुर-नगवा-बुढाना-शामली को निरस्त करने का निर्णय लिया गया। सम्भाग के ऑटो-टैम्पो के 06 माह से अधिक विलम्ब से प्राप्त 08 प्रार्थना पत्रों पर विचार करते हुए परमिट नवीनीकरण की स्वीकृति प्रदान की गयी।मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा-86 के अन्तर्गत 03 वाहनों पर विचार करते हुए 03 चालानो पर 10,000/- रू0 अर्थदण्ड व 01 माह के लिए परमिट निलम्बित किया जाए और 04 से अधिक 09 चालान होने पर 20,000/- रू0 अर्थदण्ड तथा 01 माह के लिए परमिट निलम्बित किये जाने का निर्णय लिया गया।यू.पी.11ए.टी.-4952 के परमिट संख्या- 2023-एनपी-9138डी परमिट को निरस्त करने का निर्णय लिया गया। जनपद शामली में ऑटो के केन्द्र निर्धारित किये जाने हेतु जिलाधिकारी, शामली से अभिमत प्राप्त करने के निर्देश दिये गये। परमिट शर्तों के विरूद्ध पाये गये 02 ऑटो परमिट धारकों पर नियमानुसार शमन शुल्क वसूल किये जाने के निर्देष दिये गये। ई-रिक्षा के सुलभ संचालन हेतु मार्गों को निर्धारित किये जाने के निर्देश दिये गये। इसके अतिरिक्त अन्य बिन्दुओं पर वाहन स्वामियों के प्रत्यावेदनों पर सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिये गये। बैठक में जिलाधिकारी सहारनपुर/सदस्य, संभागीय परिवहन प्राधिकरण मनीष बंसल , उप परिवहन आयुक्त मेरठ परिक्षेत्र मेरठ/सदस्य संभागीय परिवहन प्राधिकरण, हरिशंकर सिंह, संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन)/सचिव, संभागीय परिवहन प्राधिकरण देवमणि भारतीय, आमन्त्रित सदस्य वी0के0 सिंह, संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), सहारनपुर एवं सम्भाग के सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), यात्रीकर अधिकारी उपस्थित रहें।

अवैध रेत उत्खनन एवं परिवहन पर सख्त कार्रवाई हेतु पुलिस और खनिज विभाग की संयुक्त बैठक आयोजित

अनूपपुर जिले में अवैध रेत उत्खनन और परिवहन को रोकने के लिए पुलिस और खनिज विभाग की एक महत्वपूर्ण संयुक्त बैठक का आयोजन पुलिस अधीक्षक कार्यालय में किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता पुलिस अधीक्षक अनूपपुर, श्री मोती उर रहमान ने की। बैठक में संचालक खनि प्रशासन श्रीमती आशालता वैद्य, खनिज निरीक्षक श्रीमती ईशा वर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री इसरार मंसूरी, एसडीओपी अनूपपुर श्री सुमित किरकेट्टा और जिले के सभी थाना प्रभारी उपस्थित रहे।

बैठक में लिए गए प्रमुख निर्णय

1 . संयुक्त कार्रवाई पुलिस और खनिज विभाग आपसी समन्वय के साथ अवैध रेत उत्खनन और परिवहन रोकने के लिए लगातार संयुक्त कार्रवाई करेंगे। सभी थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया कि अवैध उत्खनन के संभावित घाटों एवं स्थान पर रात्रि में पुलिस पेट्रोलिंग पार्टी भेजी जाएगी जो ऐसे स्थान पर सतत निगरानी रख कार्रवाई करेंगे।

2. आदतन आरोपियों पर निगरानी अवैध रेत चोरी और परिवहन में संलिप्त आदतन आरोपियों की जानकारी साझा कर उनकी गतिविधियों पर निगरानी रखी जाएगी और सख्त कार्रवाई होगी।

3. छत्तीसगढ़ से जारी ISTP के दुरुपयोग की जांच ई-खनिज पोर्टल से जारी ISTP (इंटर स्टेट ट्रांजिट पास) के दुरुपयोग की जांच होगी। खासतौर पर छत्तीसगढ़ की ISTP का मध्यप्रदेश में अवैध परिवहन के लिए दुरुपयोग पाए जाने पर धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज किए जाएंगे।

4. अवैध खदानों पर विशेष निगरानी जिले में बिना स्वीकृति वाली खदानों की निगरानी के लिए विशेष दल गठित किया जाएगा ताकि अवैध रेत उत्खनन और परिवहन पर रोक लग सके।

5. जिला बदर कार्रवाई अवैध रेत उत्खनन और परिवहन करने वाले आरोपियों के खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी।

6. समन्वित जानकारी पुलिस द्वारा अवैध रेत उत्खनन और परिवहन के प्रकरण दर्ज करने पर समय पर खनिज विभाग को सूचित किया जाएगा ताकि खनिज विभाग भी आवश्यक कार्रवाई कर सके।

सख्त निर्देश जारी पुलिस अधीक्षक अनूपपुर ने सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिए कि उनके थाना क्षेत्रों में अवैध रेत उत्खनन और परिवहन रोकने के लिए विशेष टीम गठित की जाए और प्रतिदिन कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

बैठक में उपस्थित अधिकारी थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक अरविंद जैन, थाना प्रभारी जैतहरी प्रकाश कोल , थाना प्रभारी कोतमा सुंदरेश मरावी, थाना प्रभारी बिजुरी विकास सिंह, थाना प्रभारी भालूमाड़ा राकेश सिंह , थाना प्रभारी रामनगर अमर वर्मा, चौकी प्रभारी वेंकटनगर उपनिरीक्षक अमरलाल यादव, और चौकी प्रभारी फुनगा सुमित कौशिक। पुलिस और खनिज विभाग की इस समन्वित कार्रवाई का उद्देश्य जिले में अवैध रेत उत्खनन और परिवहन पर पूर्णत: रोक लगाना है।

स्वास्थ्य विभाग का मैदानी अमला सक्रिय रूप से योजनाओं कार्यक्रमों एवं अभियान का करें बेहतर क्रियान्वयन-कलेक्टर

कलेक्टर ने की स्वास्थ्य विभाग के कार्यों के प्रगति की समीक्षा

सुशिल सोनी । सिटी चीफ

अनूपपुर, कलेक्टर श्री हर्षल पंचोली ने कहा है कि स्वास्थ्य विभाग का मैदानी अमला संवेदनशीलता एवं गंभीरता के आधार पर शासन द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं, कार्यक्रमों एवं अभियान का बेहतर क्रियान्वयन करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि जिले की सभी एएनएम एवं आशा कार्यकर्ता एक्टिव होकर कार्य करें। गंभीर बीमारी के चिन्हित मरीजों की जांच एवं उपचार शासन के निर्धारित मापदंडों के अनुसार समय में करना सुनिश्चित किया जाए। कलेक्टर ने कहा कि एएनम एवं आशा कार्यकर्ता द्वारा किए जा रहे कार्यों की गंभीरता से मॉनिटरिंग एवं समय-समय पर बैठकें आयोजित कर कार्यों की समीक्षा खंड चिकित्सा अधिकारी करें। कलेक्टर श्री हर्षल पंचोली आज कलेक्ट्रेट स्थित नर्मदा सभागार में स्वास्थ्य विभाग के कार्यों की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देशित कर रहे थे। बैठक में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. ए.के. अवधिया, सिविल सर्जन तथा जिले के सभी खंड चिकित्सा अधिकारी सहित स्वास्थ्य विभाग का अमला उपस्थित था। बैठक में कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिला एवं खंड चिकित्सालय में बेहतर साफ सफाई व्यवस्था हो तथा चिकित्सालय आकर्षित तरीके से दिखाई दे। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग व्यवस्थित तरीके से स्वास्थ्य सेवाओं का संचालन करें तथा मरीजों को बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराएं। बैठक में कलेक्टर ने जिला चिकित्सालय के एएनसी वार्ड में गर्भवती माताओं के पंजीयन, संस्थागत प्रसव तथा होम डिलीवरी की जानकारी प्राप्त की। इस दौरान कलेक्टर ने परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत नसबंदी तथा राष्ट्रीय अंधत्व नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत किए गए ऑपरेशन के संबंध में भी चर्चा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर ने बच्चों के टीकाकरण की जनपदवार जानकारी प्राप्त की तथा टीकाकरण कर शासन के निर्धारित मापदंडों के अनुसार गंभीरता से कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत मलेरिया एवं डेंगू, जिले में मातृ एवं शिशु मृत्यु दर, सिकल सेल उन्मूलन कार्यक्रम के तहत चिन्हित मरीज एवं ऐसे मरीज जो स्वयं विधिवत रूप से उपचार नहीं करा रहे हैं, ऐसे मरीजों की सूची संधारित कर उनका इलाज करने के निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर ने जिले में सिकल सेल एनीमिया से हुए मृत्यु के संबंध में भी अधिकारियों से जानकारी प्राप्त की। बैठक में कलेक्टर ने खंड चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित किया कि जिले में सिकल सेल एनीमिया की जांच प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। इसके लिए सुपरवाइजर, एएनएम तथा आशा कार्यकर्ता मैदानी स्तर पर एक्टिव होकर कार्य करें। उन्होंने आयुष्मान कार्ड के प्रगति की भी समीक्षा की। बैठक में कलेक्टर ने राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम के तहत किए जा रहे उपचार एवं लक्ष्य की जानकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से प्राप्त की तथा निर्देशित किया कि क्षय रोग के चिन्हित मरीजों की स्थिति एवं दवाई वितरण समय पर हो तथा गंभीर बीमारी के मरीजों के घर जाकर उन्हें दवा प्रदान किया जाए तथा इसकी मॉनीटरिंग भी की जाए। बैठक में कलेक्टर ने जननी सुरक्षा योजना, सीएम हेल्पलाइन प्रकरण, सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में भर्ती किए गए बच्चों की जानकारी सहित अन्य विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते हुए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

सोन की सुनहरी रेत की जारी कालाबाजारी

कार्यवाही : 06 पर एफआईआर, तीन ट्रैक्टर जप्त

मोहम्मद मुनीर । सिटी चीफ
शहडोल, आदिवासी अंचल में सुनहरी रेत का काला कारोबार रुकने का नाम नहीं ले रहा है, जिले में माफियाओ का बड़ा कद का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ रेत माफियाओ ने ट्रैक्टर से कुचलकर पटवारी एवं सहायक उप निरीक्षक की हत्या कर दी थी, बावजूद बदस्तूर जारी अवैध रेत खनन अभी भी जारी है। आखिरकार अब पुलिस ने कार्यवाही कर यह साबित कर दिया कि अवैध रेत क्षेत्र से निकली जा रही है।

शहडोल। ब्यौहारी थाना पुलिस ने बीती रात्रि रेत का अवैध उत्खनन कर परिवहन करते तीन ट्रैक्टरों को जप्त कर 6 लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज किया है, पुलिस ने तीन ट्रैक्टर चालकों को गिरफ्तार कर वाहन मालिक की तलाश कर रही है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर बीती रात्रि नगर से पुलिस ने यह कार्रवाई को अंजाम दिया है। मिली जानकारी के अनुसार झापर नदी से रेत का अवैध खनन का तीन ट्रैक्टरों में इसका परिवहन किया जा रहा था, तीनों ट्रैक्टर ब्यौहारी नगर में रेत डंप करने पहुंचे तभी बीती रात्रि पुलिस की विशेष टीम ने घेराबंदी कर तीनों ट्रैक्टरों को रेत सहित जप्त कर कारवाही की है। तीन चालकों को पुलिस ने मौके से गिरफ्तार किया है। इस मामले में कुल छह आरोपी बनाए गए हैं जिसमें ट्रैक्टर चालक एवं वाहन मालिक शामिल है। पुलिस अधीक्षक राम जी श्रीवास्तव के निर्देश पर थाना प्रभारी ब्यौहारी अरुण पांडे की टीम ने इस कार्यवाही को अंजाम दिया है। थाना प्रभारी ने बताया कि बीती रात मुखबिर की सूचना पर कार्यवाही को अंजाम दिया है, मुखबिर के द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि नगर में अवैध रेत डंप करने तीन ट्रैक्टर आ रहे हैं। तभी पुलिस ने नगर में घेराबंदी का तीनों ट्रैक्टरों को जप्त कर चालकों को गिरफ्तार किया है, वाहन मालिक भी इस मामले में आरोपी बनाए गए हैं। 6 लोगों के विरुद्ध अपराध दर्ज कर कारवाही की गई है।जिसमें खनिज अधिनियम व अन्य धाराओं पर मामला दर्ज किया गया है।

18 एकड़ वनरक्षित भूमि पर अभिषेक ने किया कब्ज़ा

शिकायतकर्ता का तर्क माफिया का आतंक वनभूमि असुरक्षित, कलेक्टर, डीएफओ सहित सीएम को हुई शिकायत

मोहम्मद मुनीर । सिटी चीफ ।
उमरिया। जिले में जंगली जानवरो का रहवासी इलाके में बढ़ता दखल कही ना कही बतलाता है की मानव ने जंगली जानवरो की शांति में खलल पैदा कर दिया जिससे नाराज जंगली जानवरों का रहवासी इलाके में मूवमेंट की खबर आई दिन सुनने और देखने को मिलती है, इसी माह की शुरुआत में जिले के बांधवगढ़ में 11 हाथियों की मौत के बाद अब जंगली हाथियों के तांडव से हड़कंप मचा हुआ है हाथियों ने रतन यादव नाम के बुजुर्ग को कुचल कर मार डाला था, वही छुहाई टोला निवासी भैरव कोल पर भी हाथियों ने हमला कर दिया। उसकी घटनास्थल पर ही जान चली गई। उमरिया और शहडोल जिले की सीमा पर सोन नदी के किनारे देखे गए जंगली हाथियों में कुछ नए बच्चे भी होने की जानकारी सामने आई है। बताया गया है कि सोन नदी के किनारे रेत पर कुछ छोटे बच्चों के पगमार्क दिखाई दिए हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि मादा हाथियों ने बच्चों को जन्म दिया होगा। अब भला जंगली जानवरो की भूमि पर कब्जा कर भूमाफिया का काला कारोबार भले ही चल निकला हो लेकिन आज पर्यावरण एवं इंसानी जीवन एक बड़ा खतरे के दौर से गुजर रहा है, जिसमे इंसानी और जानवरो के बीच संघर्ष की खबरे आम हो रही है। जिसको लेकर सूबे के मुख्यमंत्री ने दो टूक में वन परिक्षेत्र से लेकर

जिला प्रशासन के अमले को चेताया है।

हुआ ऐसे फर्जीवाड़ा... इस घटनाक्रम के मद्देनजर मामले की गंभीरता को भांपते हुए समाजसेविका गीता सिंह परिहार में जंगली जानवरो और इंसानी दखल का पुलिंदा खोल कर रख दिया है प्रमाणित आरटीआई से मांगे दस्तावेजों के आधार पर घुनघुटी की अठारह एकड़ भूमि पर कथित भूमाफिया अभिषेक मिश्रा ने कब्ज़ा जमाया हुआ है इतना ही नहीं एक फर्जी तरीके से निष्पादित पट्टा खसरे में इंट्री इत्यादि करवा ली गई है, जिसे देखने के बाद अच्छे अच्छे भूमाफिया के झांसे में फसते चले जा रहे है ताज़ा मामला संज्ञान में तब आया जब इस भूमाफिया में एक पुलिस कर्मी को ही अपना शिकार बना लिया, इस करतूत का पता तब चला जब पुलिस कर्मी को इस भूमि में लोन लेने के उद्देश्य से बैंक में कागज रहे जिसकी पड़ताल में बैंक कर्मियों इस भूमि और बेचने वाले की करतूत को खोज निकाला।

निगहबानों ने बेचा इमां... गौरतलब है की घुनघुटी की अठारह एकड़ भूमि प्रमाणित दस्तावेजों में वनरक्षित भूमि है जिसका किसी भी तरह से हस्तांतरण किया जाना संभव नहीं है बावजूद भूमाफिया ने वनभूमि कब्ज़ा करते हुए बिक्री कर रही है, अब देखना यह होगा की वन्य प्राणी के विचरण की भूमि कब्ज़ा करने वालो से जिम्मेदार अमला कब तक अपनी भूमि कब्ज़ा मुक्त करा पाता है अथवा भूमाफिया के आगे घुटने तक देता है। हालांकि मामले में भारत सरकार की वनरक्षित भूमि सुनियोजित तरीके से कुछ राजस्व अमले को इस फर्जीवाड़े के सिंडिकेट में शामिल करते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग के इर्दगिर्द की भूमि भूमाफिया हड़प कर बैठे है, और इस मामले में आश्चर्य जनक बात यह है की उस जमीन को भूमाफिया साहूकार बनकर तहसील कार्यालय में लोगो की मदद से बेच रहा है, अब जिले के शीर्ष अधिकारियो को हुई शिकायत को महीनो गुजर जाये तो इस मामले में किसी बड़े भूमाफिया के सिंडिकेट में किस किस की कितनी भागीदारी है तलाशने की आवश्यकता होगी, वरना भारत सरकार की वन भूमि इतने बड़े पैमाने पर हड़पकर विधिवत क्रय बिक्री करना इतना आसान नहीं होता सर शब्दो में घुनघुटी के जंगलो के निगहबानों ने ही वन्य प्राणी के विचरण की भूमि बेच डाली, और आज बेकसूर आये दिन दम तोड़ रहे है, मामले में जिम्मेदारों को शिकायत के बाद भी एक भूमाफिया को प्रोटेक्ट करने के पीछे की वजह भी समझ से परे है।

इनका कहना है।
मैंने अभी पूरे पेपर देखा नहीं है, आपकी शिकायत में निश्चिंत रहिये कार्यवाही होगी, मैं कोई मैनेज नहीं होने वाला, निष्पक्ष जाँच कार्यवाही होगी।
अर्जुन सिंह बाजवा, रेंजर
वन परिक्षेत्र, घुनघुटी

आउटसोर्स के माध्यम से भर्ती पर चतुर्थ श्रेणी लघु वेतन कर्मचारियों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन

भगवान दास बैरागी । सिटी चीफ
शाजापुर, आउटसोर्स के माध्यम से विभागों में भर्ती प्रक्रिया के विरोध में चतुर्थ श्रेणी लघु वेतन कर्मचारियों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। गुरुवार को मुख्यमंत्री के नाम सौंपे गए ज्ञापन में बताया कि राज्य शासन के विभिन्न कार्यालयों में चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों के विरूद्ध कार्य करने के लिए व्यक्तियों की पूर्ति हेतु वित्त विभाग के संदर्भित पत्र में मुख्य रूप से आउटसोर्स पर चतुर्थ श्रेणी कार्मिक की सेवाएं प्राप्त करने संबंधी नीति निर्देश हैं, जिसके तहत विशिष्ट विभाग जहां चतुर्थ श्रेणी के पदों पर सीधी भर्ती अति आवश्यकता है वहां वित्त विभाग को तथ्यों सहित प्रस्ताव प्रेषित करते हुए स्वीकृति प्राप्त करने को कहा गया है। उपरोक्त निर्णय से शासकीय कार्य की गति प्रभावित होने के साथ-साथ ऐसे युवा जो आठवीं एवं दसवीं तक की शिक्षित हैं शासकीय सेवा से वंचित होंगे। प्रदेश

के युवाओं का एक बड़ा हिस्सा जो कम शिक्षित है वह चतुर्थ श्रेणी के पदों पर सीधी भर्ती का अवसर प्राप्त नही कर पाएगा। आउटसोर्स से पदों की पूर्ति प्राईवेट ऐजेंसियों के माध्यम से भर्ती की जाती है जिसका कोई बुनियादी भविष्य नही है। ऐसे में प्राईवेट ऐजेसियों के माध्यम से पदों को न भरते हुए शासन द्वारा रिक्त पदों भरा जाए। इस मौके पर मप्र लघु वेतन कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष टीकाराम कुशवाह, गोविन्दसिंह भदोरिया, अमृतलाल मीणा, अजय शिन्दे, शैलेन्द्र, जमनालाल, अन्तरसिंह, श्यामलाल, सुभाष, सचिन, आत्माराम, नन्दकिशोर वर्मा, रमेश वर्मा, ओमप्रकाश, सन्तोष, अजय मालवीय, लक्की, बहादुर, धर्मेंद्र, जितेन्द्र, अजय राठौर, संदीप, तूफानसिंह, मोहन रॉय, सुरेश वर्मा, ओम वर्मा, कैलाश जाटव, अमर वर्मा, मनीषा, रेखा, कृष्णाबाई उपस्थित थे।

बीजोत्पादक समितियां उद्यानिकी फसलों के बीजोत्पादन के क्षेत्र में आगे आएं-कलेक्टर

भगवान दास बैरागी । सिटी चीफ
शाजापुर। जिले में उद्यानिकी फसलों का रकबा निरंतर बढ़ रहा है, इसलिए बीजोत्पादक समितियां उद्यानिकी फसलों के बीजोत्पादन के लिए आगे आएं। यह बात कलेक्टर ऋजु बाफना ने गुरुवार को जिले की बीजोत्पादक समितियों एवं बीज प्रमाणीकरण अधिकारियों के साथ सम्पन्न हुई बैठक में कही। कलेक्टर ने जिले में रबी एवं खरीफ फसलों के लिए बीजोत्पादन कर रही समितियों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा कर बीजोत्पादन, प्रमाणीकरण तथा वितरण की जानकारी ली। साथ ही कलेक्टर ने बीजोत्पादन में आ रही समस्याओं के बारे में भी पूछा।

समितियों के प्रतिनिधियों ने बताया कि वर्तमान में बीजोत्पादन के लिए स्थानीय बाजार से कर्ज लेना पड़ता है, जिसकी ब्याज दरें अत्यधिक होती हैं अतः उन्हें भी बीजोत्पादन के लिए बैंकों से ऋण की सुविधा प्राप्त हो। कलेक्टर ने कहा कि इस संबंध में बैंकों से चर्चा की जाएगी। साथ ही समितियों के प्रतिनिधियों ने अन्य समस्याओं से भी अवगत कराया। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ संतोष टैगोर, उपसंचालक कृषि केएस यादव, उद्यानिकी मनीष चौहान सहित बीजोत्पादक समितियों एवं बीज प्रमाणीकरण, बीज निगम के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

727 नामांतरण के प्रकरणों का निराकरण 15 नवम्बर से 15 दिसम्बर 2024 तक आयोजित किए जा रहे राजस्व महाअभियान 3.0 में अब तक 727 नामांतरण के प्रकरणों का निराकरण हुआ है। इसी तरह बंटवारा के 71, अभिलेख दुरूस्ती के 3, सीमांकन के 3, परम्परागत रास्तों के चिन्हांकन के 10, नक्शा तरमीम के 9475, आधार से राजस्व अभिलेख खसरा लिंकिंग के 19091, फार्मर रजिस्ट्री के 5961 का पंजीयन तथा 268 ईकेवायसी एवं 135 एनपीसीआई पूर्ण किए गए हैं।

खबर प्रकाशन से तिलमिलाई कजंई हायर सेकंडरी कि शिक्षिका?

पत्रकारों ने एकजुट होकर थाना प्रभारी व विकासखंड शिक्षा अधिकारी को सौंपा कार्यवाही हेतु पत्र

लाकेश पंचेश्वर । सिटी चीफ
लालबर्रा, लालबर्रा विकासखंड क्षेत्र अंतर्गत शासकीय शालाओं में देरी से पहुंचने एवं समय से पहले शाला से जाने वाले शिक्षक-शिक्षिकाओं पर दो दिन पूर्व ही दैनिक हरिभूमि के तहसील प्रतिनिधी द्वारा गैर जिम्मेदार शिक्षक-शिक्षिकाओं के विरुद्ध ग्रामीणों की शिकायत पर समाचार प्रकाशित किया गया था,जिससे आक्रोशित होकर शासकीय उच्चतर माध्यमिक हायर सेकेंडरी विद्यालय कंजई की एक शिक्षिका ने हरिभूमि समाचार पत्र तहसील प्रतिनिधि शैलेश (राहुल) जायसवाल से फोन पर अभद्रता पूर्वक बद्तमीजी के साथ बातचीत की है एवं नईदुनिया समाचार पत्र के लालबर्रा तहसील प्रतिनिधि रविकिरण सोनी के घर पहुंच कर उक्त शिक्षिका ने अपने पति के साथ उन्हें भी धमकी दी है कि मैं विद्यालय कभी भी आऊं,जाऊं कवरेज मत करना,वरना मैं थाने में झूठी शिकायत कर तुमको फंसा दूंगी।क्षेत्र में चल रही अव्यवस्थाओं पर शासन-प्रशासन का ध्यान आकर्षित कराना पत्रकारों का दायित्व है। ऐसे में उक्त शिक्षिका द्वारा अपने पति के साथ पत्रकारों के घर पहुंचकर अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करना व खबर प्रकाशित न करने की धमकी देना हम सभी पत्रकारों के अधिकारों का हनन है। इस आशय का लिखित आवेदन थाना प्रभारी हेमंत नायक के नाम देकर

सभी पत्रकारों ने उक्त शिक्षिका पर नियमानुसार विधिवत उचित कार्यवाही करने हेतु निवेदन किया है।

विकासखंड शिक्षा अधिकारी को भी सौंपा ज्ञापन विकासखंड क्षेत्र अंतर्गत शालाओं में देरी से पहुंचने वाले एवं निर्धारित समय से पूर्व शाला छोड़ने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई बाबत तहसील क्षेत्र के सभी पत्रकार साथियों ने विकासखंड अंतर्गत शासकीय शालाओं के शासन द्वारा निर्धारित शाला समय के उपरांत शिक्षकों के लेट लतीफी के चलते देरी से खुलने व समय के पूर्व शाला बंद होने संबंधी काफी शिकायत स्थानीय ग्रामीणों के माध्यम से निरंतर पत्रकारों को की जा रही है। ग्रामीणों से प्राप्त शिकायत के आधार पर लालबर्रा तहसील क्षेत्र के पत्रकारों द्वारा विभिन्न समाचार पत्रों व न्यूज़ चैनलों में लापरवाही बरतने वाले शिक्षकों के खिलाफ समाचारों का प्रकाशन कर शासन-प्रशासन का ध्यान आकर्षण किया जा रहा है। कतिपय मामलों में यह देखा जा रहा है कि बालाघाट या अन्य स्थान से बस या मोटरसाइकिल स्कूटी से कुछ शिक्षक-शिक्षिकाएं शाला आना जाना करते हैं। जिसके कारण न ही निर्धारित समय पर शाला पहुंचते हैं और न ही निर्धारित समय तक शाला में रुकते हैं। इसके अलावा जिन अधिकारियों को शालाओं की मॉनिटरिंग का जिम्मा है वह भी नियमित रूप से शालाओं का निरीक्षण नहीं कर रहे हैं,जिससे बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो रहा है। वहीं पर बहुत सी शालाएं ऐसी है जहां पर पदस्थ शिक्षक-शिक्षिकाएं नियमानुसार अच्छा कार्य कर रहे हैं।समस्त पत्रकारों ने विकासखंड शिक्षा अधिकारी से निवेदन किया है कि शाला में देरी से पहुंचने वाले एवं समय से पूर्व घर जाने वाले अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाह शिक्षक-शिक्षिकाओं की नियमित जांच कर कार्यवाही करने का कष्ट करें,क्योंकि कुछ लापरवाह शिक्षकों के कारण अच्छा कार्य करने वाले शिक्षक भी कोप भाजन का शिकार बन रहे हैं।

नाबालिग छात्रों द्वारा दोपहिया वाहन चलाने के विरुद्ध कोतवाली अनूपपुर पुलिस की सख्त कार्रवाई

यशपाल सिंह जाट । सिटी चीफ
अनूपपुर, जिले में नाबालिग छात्रों द्वारा तेज गति और लापरवाही से दोपहिया वाहन चलाने की बढ़ती शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक अनूपपुर, श्री मोती उर रहमान ने तत्काल कार्रवाई के निर्देश जारी किए।

गुरुवार सुबह थाना कोतवाली प्रभारी अरविंद जैन के नेतृत्व में सहायक उपनिरीक्षक गोविंद पनिका, प्रधान आरक्षक शिवशंकर प्रजापति, आरक्षक गोपाल यादव, राजेश बड़ोले और गिरीश चौहान की टीम ने भारत ज्योति स्कूल के पास वाहन चेकिंग अभियान चलाया।

इस अभियान के दौरान छह नाबालिग छात्रों को बिना वैध लाइसेंस और नियमों के उल्लंघन करते हुए दोपहिया वाहन चलाते पाया गया। इनके वाहन विवरण निम्नलिखित हैं-

1. होंडा लीवो (एमपी 65 एमबी 9289)
2. टीवीएस ज्यूपिटर (एमपी 65 एस 3014)
3. होंडा मोटरसाइकिल (एमपी 65 एमडी 8664)
4. हीरो सुपर स्प्लेंडर (एमपी 65 एमई 6615)
5. मोटरसाइकिल (एमपी 65 एमडी 0639)
6. बिना नंबर की एक्टिवा मोपेड

इन वाहनों को मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जप्त कर चालान की कार्रवाई की गई है।

पुलिस अधीक्षक महोदय अनूपपुर की अपील पुलिस अधीक्षक अनूपपुर श्री मोती उर रहमान ने अभिभावकों से अपील की है कि वे अपने 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को वाहन चलाने की अनुमति न दें। ऐसा करना न केवल गैरकानूनी है, बल्कि इससे सड़क दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ जाता है। बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी अभिभावकों से कानून का कड़ाई से पालन करने का अनुरोध किया गया है।पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने की घटनाओं को रोकने के लिए चेकिंग और कार्रवाई जारी रहेगी।

आदिवासी छात्र आत्महत्या के मामले को लेकर आप पार्टी ने किया जय स्तंभ चौक में चक्काजाम

गणेश वैष्णव | सिटी चीफ

छत्तीसगढ़। नारायणपुर, आम आदमी पार्टी के नेताओं ने जांच अधिकारी से तिखे सवाल दागे आईएएस अधिकारी एसडीएम जैन को उल्टे पैर भगना पड़ा - सुरजीत ठाकुर जिला अध्यक्ष आम आदमी पार्टी नारायणपुर जिला प्रशासन नारायणपुर मंत्री केदार कश्यप के दबाव में कर रही है काम अब तक जांच नहीं आरोपियों को बचाने में लगी है बीजेपी के नेता -महेर सिंह वट्टी प्रदेशाध्यक्ष एसटीविंग आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ लगातार आप पार्टी के द्वारा बालक बुनियादी आदर्श छात्रावास गरांजी के अध्ययनरत छात्र योगेंद्र वट्टी जो हास्टल अधीक्षक ओंकार सिंह ठाकुर के प्रताड़ना से फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया। आम आदमी पार्टी नारायणपुर की टीम पूर्व में जाकर निरीक्षण करने के दौरान बच्चों से मुलाकात कर जानकारी लिया पता चला कि हॉस्टल के बच्चों को हॉस्टल अधीक्षक ओंकार द्वारा बच्चों से मारपीट गाली गलोच अभद्र व्यवहार किया जाता है। योगेंद्र वट्टी छात्र जो अत्महत्या करने से एक दिन पहले उसको अधीक्षक ने लोहा से मारा था आम आदमी पार्टी ऐसे अत्याचारी अधीक्षक की घोर निंदा करते हुए शासन प्रशासन से यही मांग करती हैं कि अधीक्षक के ऊपर जल्द से जल्द जांच कर कड़ी कार्यवाही के साथ हटाया जाए। आप पार्टी द्वारा पूर्व में ज्ञापन दिया गया था जिसे प्रशासन द्वारा आश्वाशन दिया गया जांच टीम बनाकर कारवाही की जायेगी किंतु अब तक हास्टल अधीक्षक व आत्महत्या की जांच पूर्ण नही होने के कारण आप पार्टी द्वारा उग्र होकर जय स्तंभ में चक्काजाम किया व शासन प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर जल्द अधीक्षक पर कारवाही की मांग कर मृतक छात्र को न्याय दिलाने चक्काजाम के बाद प्रशासनिक अधिकारी एवं पुलिस को ज्ञापन दिया गया। इस दौरान आप पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी एवम कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

नगर पालिका के कर्मचारी चले गए हड़ताल पर

नगर की व्यवस्था का हो गया बेहाल.....

गणेश वैष्णव | सिटी चीफ

छत्तीसगढ़। नारायणपुर, नारायणपुर बीते एक सप्ताह से नगर पालिका के कर्मचारी वेतन बढ़ोतरी और संविलियन को लेकर बखरुपारा के हड़ताल स्थल पर धरना देने को मजबूर हो गए हैं। नगर की व्यवस्थायें को देखा जाए तो कई नालियाँ में पानी जाम की स्थिति बनी हुई है और नगर में यहां वहां गंदगी से नगर का हाल बेहाल हो गया है।नगर के रहवासी पानी की कमी और कुड़ा करकट के अस्त व्यस्त होने से काफी ज्यादा परेशान हो गए हैं। कर्मचारियों का कहना है कि जब तक सरकार हमारी माँगे पूरी नहीं करती तब तक हम हड़ताल से नहीं हटेंगे, सरकार को अल्टीमेटम दिया गया है कि हमारी मांगे यदि पूरी नहीं होती है तो और भी उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। यदि इसी प्रकार से हड़ताल पर रहे तो नगर की व्यवस्था और भी बेहाल हो जाएगी।

19 खेलो में होगा खेलो एमपी यूथ गेम्स 2024, तैयारियों को लेकर बैठक आयोजित

भगवान दास बैरागी | सिटी चीफ शाजापुर। खेलो इण्डिया की तर्ज पर खेलो एमपी यूथ गेम्स 2024 द्वितीय संस्करण में जिले में खण्ड एवं जिला स्तरीय 19 खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। खेल प्रतियोगिताओं की रूपरेखा तैयार करने के लिए गुरुवार को कलेक्टर ऋजु बाफना एवं पुलिस अधीक्षक यशपाल सिंह राजपूत की मौजूदगी में कलेक्टर सभाकक्ष में बैठक सम्पन्न हुई। कलेक्टर बाफना ने खेल प्रतियोगिताएं स्कूली विद्यार्थियों की परीक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए आयोजित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने मुख्य नगरपालिका अधिकारी को स्टेडियम में आवश्यक व्यवस्था करने के निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक एवं खेल विभाग के नोडल अधिकारी राजपूत ने खेलो एमपी यूथ गेम्स 2024 की प्रतियोगिताओं में पूर्णत- पारदर्शिता रखने के निर्देश दिए। इस दौरान जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारी रविन्द्र हार्डिया ने खेलो एमपी यूथ गेम्स 2024 के अंतर्गत विकासखण्ड स्तर पर होने वाली चयन स्पर्धा एवं जिलास्तर पर होने वाली 19 खेलों की खेल प्रतियोगिताओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होने बताया कि 01 से 11 दिसम्बर 2024 तक जिले के प्रत्येक विकासखण्ड स्तर पर चयन स्पर्धा का आयोजन किया जाएगा। जिला मुख्यालय पर बालिका वर्ग एवं बालक वर्ग की प्रतियोगिता आयोजित किए जाने का निर्णय लिया गया है। विकासखण्ड स्तर पर आयोजित होने वाली चयन स्पर्धा में खेलों का चयन ट्रायल किया जाएगा, जिसमें एथलेटिक्स, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, बॉक्सिंग, फुटबॉल, हॉकी, जूडो, कबड्डी, खोखो, मलखम्ब, तैराकी, वेटलिफ्टिंग, कुश्ती, टैबल-टेनिस, योगासन, व्हॉलीबॉल, क्रिकेट एवं शतरंज में किया जाएगा। खेलो एमपी यूथ गेम्स 2024 की चयन स्पर्धा मे भाग लेने वाले खिलाड़ियों को पंजीयन कराना अनिवार्य है। पंजीयन फार्म के साथ पासपोर्ट साईज फोटो, मूल निवासी, आधारकार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, अध्ययनरत कक्षा की मार्कशीट संलग्न करना अनिवार्य है। बिना दस्तावेजों के पंजीयन फार्म स्वीकार नहीं किया जाएगा। भाग लेने वाले प्रतिभागियों की आयु 31 दिसंबर 2024 की स्थिति में 19 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए।

सशक्त पत्रकार समिति की बाइक महारैली में उमड़ा पत्रकारों का जनसैलाब, प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, पूर्व मुख्यमंत्री ने मीडिया सेंटर बनाने का पत्रकारों से झूठा वादा किया, इसे मोहन सरकार पूरा करे, मांगे पूरी नहीं होने पर करेंगे बड़ा आंदोलन

पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने सहित 10 सूत्री मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम दिया ज्ञापन, विभिन्न सामाजिक संगठनों ने पुष्प वर्षा कर पत्रकारों का किया स्वागत।

बुरहानपुर। सशक्त पत्रकार समिति के अंतर्गत पत्रकारों की विभिन्न लंबित 10 सूत्री मांगों को लेकर प्रदेश अध्यक्ष उमेश जंगाले के नेतृत्व में द्वितीय वर्ष भी पत्रकारों द्वारा बाइक महारैली निकाली गई, जिसमें शहर व ग्रामीण से बड़ी संख्या में पत्रकार शामिल हुए। सर्व प्रथम मां सरस्वती के तेल चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किया गया। तत्पश्चात् बाइक महारैली को पूर्व विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह, प्रसिद्ध कथा वाचक श्री हरिकृष्ण मुखियाजी, कांग्रेस जिला अध्यक्ष रिंकू टांक, अखिल भारतीय मजदूर ट्रेड यूनियन के प्रदेश महामंत्री कालू जंगाले ने हरी झंडी दिखाकर शाही किले से रैली का शुभारंभ कर रैली को रवाना किया। जिसके बाद हमारी मांगे पूरी करो के नारों से शहर गूंज उठा। इसके बाद पत्रकारों की रैली का गांधी चौक, फूल चौक कमल तिराहा सहित विभिन्न मार्गो पर विभिन्न सामाजिक संगठनों एवं जनप्रतिनिधियों जिसमें जायंट्स ग्रुप ऑफ बुरहानपुर सेवन के यूनिट टू डायरेक्टर महेंद्र जैन एवं जनजागृति संस्था के अध्यक्ष सुनील सलूजा, रमेश चंद्र शर्मा, राकेश श्रीवास्तव, अखिल भारतीय मजदूर ट्रेड यूनियन के प्रदेश महामंत्री कालू जंगाले, अजय परोचे, मनोज करोसिया, मनोज कन्नाडे, प्रमुख पेंशनर्स एसोसिएशन के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं जिला अध्यक्ष अताउल्ला खान, जिला सचिव उमेश तिवारी, मैक्सविन ह्यूमन केयर फाउंडेशन, (एन.जी.ओ) के प्रदेश अध्यक्ष, लारेब एजाज़, जिला अध्यक्ष महेश शर्मा, गीत गाता चल संस्था अध्यक्ष पराग शुक्ला, एकता समिति अध्यक्ष अकरम पठान ने पुष्प वर्षा से पत्रकारों का स्वागत किया। इस अवसर पर पत्रकारों ने मुख्यमंत्री मोहन यादव के नाम अपर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। सशक्त पत्रकार समिति के प्रदेश अध्यक्ष उमेश जंगाले ने बताया कि आए दिन पत्रकारों पर हमले हो रहे हैं, जिसे सरकार गंभीरतापूर्वक लेते हुए जल्द मध्य प्रदेश में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करें। उन्होंने कहा कि भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 3 अक्टूबर 2023 को स्टेट मीडिया सेंटर का भूमि पूजन कर प्रदेशभर के पत्रकारों के लिए सभी जिलों में मीडिया सेंटर बनाने की घोषणा की थी, लेकिन वह आजतक पूरी नहीं हो पाई, इससे यहीं प्रतीत होता है कि शिवराज सिंह ने पत्रकारों से झूठा वादा किया था। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार भी भाजपा की हैं, यदि मोहन सरकार चाहे तो शिवराज सिंह चौहान के झूठे वादे को प्रदेश के सभी जिलों में मीडिया सेंटर बनाकर पूरा कर सकती हैं। जंगाले ने कहा कि सरकार जल्द मांगों को पूरा करें, नहीं तो विवश होकर आंदोलन करेंगे। इस अवसर पर सशक्त पत्रकार समिति के पदाधिकारियों ने जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन पत्रकारगण, जनप्रतिनिधियों का धन्यवाद ज्ञापित किया।

10 मांग 1. मध्य प्रदेश में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू किया जाए।

2. शहर के बीचों-बीच पत्रकार भवन मीडिया सेंटर बनाकर दिया जाए।

3. पत्रकारों को शासकीय आवास आवंटित किए जावे।

4. लघु एवं मध्यम समाचार पत्रों को 2007 में राजपत्र में प्रकाशित नियमों के अनुसार 60000/- के विज्ञापन दिए जाने का प्रावधान है, जिसको बड़ाकार 200000/- के विज्ञापन 1 वर्ष में दिए जाएं।

5. पत्रकारों की मृत्यु पर आश्रित परिवारों को 400000/- की जगह 1500000/- की आर्थिक सहायता प्रदान की जाए।

6. उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पत्रकारों को नि:शुल्क बीमा योजना का लाभ दिया जा रहा हैं, उसी की तर्ज पर 10 लाख रुपए तक मध्य प्रदेश में भी नि:शुल्क पत्रकार बीमा योजना लागू किया जाए। स्वास्थ्य बीमा योजना में अधिमान्य पत्रकारों की भांति गैर अधिमान्य पत्रकारों के बीमा प्रीमियम की राशि भी शासन द्वारा समान रूप से भरी जाए।

7. अधिमान्यता की जटिल नियमावली में संशोधन कर सरल नियमावली बनाकर सभी पत्रकारों को अधिमान्यता दी जाए।

8. किसी भी पत्रकार की थाने में शिकायत आने के बाद उस शिकायत की जांच उच्च स्तरीय अधिकारी से ही कराई जाए, एवं मध्य प्रदेश में किसी भी पत्रकार को किसी प्रकरण में कथित रूप से सलिप्त पाए जाने पर तब तक उसकी गिरफ्तारी न कि जाए जब तक कि क्षेत्र के उच्चाधिकारी द्वारा उसकी जांच पूरी न करली जाए।

9. ''श्रद्धा निधि'' में अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारों को (60 वर्ष से अधिक आयु) को 10 हजार रुपये प्रतिमाह की ''श्रद्धा निधि'' दी जा रही है। श्रद्धा निधि योजना में गैर-मान्यता प्राप्त वरिष्ठ पत्रकार (60 वर्ष और उससे अधिक आयु) को भी शामिल किया जाए, इसके साथ ही राशि बड़ाकर (20 हजार रुपये) किया जाए।

10. प्रदेश में पत्रकार उत्पीड़न की बढ़ रही घटनाओं पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाया जाए।

शासन द्वारा किसानों के हित में की गई फॉर्मर रजिस्ट्री किसान आईडी कार्य प्रारंभ किया गया

कुंदनपुर- शासन द्वारा किसानों के हित में की गई फॉर्मर रजिस्ट्री किसान आईडी कार्य प्रारंभ किया गया ,जिसमें कृषि भूमि स्वामी को किसान आईडी बनाना अनिवार्य है। किन्तु शासन द्वारा बनाया गया फार्मर सहायक एप सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, तथा सामलाती खातेदार के तो फॉर्म ही ओपन नहीं करता है अगर शासन को किसान द्वस्र का कार्य सही तरीके से संपन्न करवाना है तो फार्मर सहायक एप में सुधार किए बिना ये संभव प्रतीत नहीं होता है।साइट नहीं चलने किसान और कर्मचारी दोनो का टाइम बर्बाद हो रहा है पूरा दिन बैठ के 100 लोगो के कागज चेक करने के बाद 10,12 लोगों की ही आईडी बन पाती है ऐसे में शत प्रतिशत कार्य किया जाना संभव नहीं है।उक्त कार्य में लगे पटवारी सहायक पटवारी (सर्वेयर ष्ह्यष) के साथ साथ किसान भी परेशान हो रहे है । रवि का सीजन चल रहा है और किसान फार्मर आईडी बनाने के लिए अपनी बारी का इंतजार करते रहते है।पूरा पूरा दिन निकल जाता है। कार्य नहीं होने पर उनके खेती बाड़ी का कार्य भी प्रभावित हो रहे है।कुंदनपुर क्षेत्र ककरादरा बड़ा , लंबेला,भंडाखेड़ा, नाहरपुरा, गलती ,खेड़ा, सुरडिया रेता, पटवारी कार्यालय पर किसने की भारी भीड़ देखी जा रही है, पटवारी सहायक भी गांव गांव फलिया फलिया जाकर बड़ी उमंग के साथ फार्मर आईडी का कार्य कर रहे हैं। साइट नहीं चलने से निराशा हाथ लग रही है।

खजराना पुलिस के सामने घुटने टिकाने लगे अपराधी

इंदौर- मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के निर्देश पर मध्य प्रदेश पुलिस अपराधियों को सबक सिखाने के लिए लगातार एक अच्छा प्रयास कर रही हैं बात करें हम इंदौर की खजराना पुलिस ने वास्तविकता में अपराधियों के घुटने टीका दिए, अपराधी बोलने लगे हाय अल्लाह अरे भगवान माफ करो अब कभी भी किसी निर्दोष व्यक्ति को परेशान नहीं करेंगे, आइए पूरी घटना से अवगत कराते क्या है मामला थाना खजराना पुलिस के द्वारा पकड़े गए चाकू बाजी अवैध वसूली करने वाले दो अपराधी। घटनास्थल की तस्दीक करने के दौरान आरोपियों ने कान पड़कर मांगी माफी कहां मेहनत करके खाएंगे चाकू नहीं चलाएंगे अज्ञात आरोपियों की तलाश में 50 से अधिक सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए और आरोपियों को ज्ञात किया इंदौर शहर मे अपराध एंव अपराधियों पर नियत्रण हेतु प्रभावी कार्यवाही के निर्देश पुलिस आयुक्त नगरीय इंदौर संतोष कुमार सिंह, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अमित सिंह, पुलिस उपायुक्त झोन 02 अभिनय विश्वकर्मा, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त झोन 02 अमरेन्द्र सिंह, सहायक पुलिस आयुक्त खजराना कुंदन मण्डलोई द्वारा दिये गये है इसी तारतम्य में उक्त निर्देशों के अनुक्रम में खजराना थाना प्रभारी मनोज सिंह सेधव द्वारा पुलिस टीम गठित कर लगातार संदिग्धों व आदतन अपराधियों की घर पकड़ की जा रही है । थाना खजराना पर फरियादी अल्ताफ के द्वारा अपराध क्रमांक 928/ 24 धारा 119 296 115 (2) 351 (2) 3 (5) व फरियादी निजाम धानक ने अपराध क्रमांक 922/24 धारा 296 115 (2) 351 (2) 3 (5) धारा का पंजीकृत कराया था दौरान विवेचना मुखबिर से सूचना मिली कि दो व्यक्ति पाकीज़ा रोड पर जा रहे है ये वही व्यक्ति है जिन्होंने चाकूबाजी और हफ्ता वसूली की घटना की है मुखबिर सूचना पर विश्वाश कर बल द्वारा त्वरित कार्यवाही कर मुखबिर के बताए स्थान पर पहुंची पुलिस को देख कर आरोपी भागने लगे जिसे पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुये, घेराबंदी कर पकड़ा। पूछताछ पर अपना नाम सोनू उर्फ अरबाज पिता परवेज खान उम्र 22 साल निवासी बाबा मसाले के आगे न्यू खिजराबाद इंदौर व दूसरे आरोपी ने अपना नाम सलमान उर्फ माडल पिता सलीम खान उम्र 20 साल निवासी चंदन नगर इंदौर होना बताया। दोनों आरोपी की जामा तलाशी लेते आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। उक्त कार्रवाई में निरीक्षक मनोज सिंह सेंधव, स उ नि राकेश परमार , प्रधान आरक्षक संजय खान प्रधान आरक्षक पंकज ,आरक्षक शशांक चौधरी की सराहनीय भूमिका रही।

मनासा पुलिस ने वेगनार कार से डोडाचूरा सहित दो आरोपी किये गिरफ्तार

मनासा- पुलिस अधीक्षक अंकित जायसवाल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एन एस सिसोदिया व एसडीओपी विमलेश उईके के निर्देशन में थाना प्रभारी मनासा निरीक्षक शिवकुमार यादव के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा मारूती वेगनआर कार से 43 किलो 735 ग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा की तस्करी करते दो युवक को गिरफ्तार किया गया है। जानकारी अनुसार दिनांक 28.11.2024 को थाना मनासा पर पदस्त सउनि0 आनंद निशाद द्वारा वाहन चैकिंग व वारंटी तलाश के दोरान एक वेगनआर कार ऋछ्व 09 ष्ट 5110 का चालक पुलिस वाहन को देखकर एकदम अल्हेड फंटे से शासकीय अस्पताल के सामने कच्चा रास्ते तरफ कार भगाने लगा जो शंका होने पर उक्त कार का पिछा करते कार चालक ने कार को रोड के साईड में पलटी खिला दी जिसे हमराह फोर्स की मदद से चालक व उसके साथ बेठे व्यक्ति को वेगनार कार से बाहर निकाला तथा नाम पता पुछते चालक ने अपना नाम नानालाल पिता ईश्वरलाल पाटीदार उम्र 30 साल नि0 काजलीखेडा व साईड में बेठे व्यक्ति ने अपना नाम शांतीलाल पिता लक्ष्मीनारायण पाटीदार उम्र 32 साल नि0 ग्राम सुपडा का होना बताया व कार की तलाशी लेते दो प्लास्टिक के कटटो मे 43 किलो 735 ग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा होना पाया गया। जिसे विधिवत जप्त कर आरोपीयों को गिरफ्तार किया गया है। तथा सम्पुर्ण कार्यवाही कर आरोपीयों के विरूध्द धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध पंजिबध्द कर विवेचना में लिया गया है आरोपीयों से डोडाचुरा के संबंध में पुछताछ जारी है।

दिल्ली के दिल में प्रदूषण से बचने का अनोखा ठिकाना

15,000 पौधों के साथ घर बन गया स्वच्छ हवा का गढ़

नेशनल डेस्क. दिल्ली, जो अपने गंभीर प्रदूषण और धुंध के लिए जानी जाती है, वहां एक ऐसा घर मौजूद है, जो न केवल खुद को प्रदूषण से बचाए रखता है, बल्कि 15,000 पौधों और आत्मनिर्भर तकनीकों के जरिए 10-15 का अद्भुत त्त्छ (वायु गुणवत्ता सूचकांक) बनाए रखता है। यह घर दिल्ली के सैनिक फार्म इलाके में स्थित है, जहां पीटर सिंह और नीनो कौर ने अपने घर को एक पर्यावरणीय स्वर्ग में बदल दिया है।

पारंपरिक निर्माण और प्राकृतिक उपायों का मिश्रण

यह घर पारंपरिक निर्माण विधियों का पालन करता है, जिसमें ईंटों को सीमेंट के बजाय चूने के मोर्टार से जोड़ा गया है। इसके अलावा, घर की दीवारों पर आधुनिक पेंट की जगह चूने का उपयोग किया गया है, जो न केवल पर्यावरण के अनुकूल है, बल्कि घर के अंदर के तापमान को भी नियंत्रित करने में मदद करता है। छत भी कंक्रीट स्लैब के बजाय पत्थर की टाइलों से ढकी हुई है, जिससे गर्मी में घर ठंडा रहता है।

पराली से खाद बनाने का अनोखा तरीका

दिल्ली में पराली जलाने से प्रदूषण का स्तर और बढ़ता है, लेकिन पीटर और नीनो ने पराली को एक संसाधन के रूप में उपयोग करने का तरीका खोज निकाला है। वे पराली को जैविक खाद के साथ मिलाकर घर में मशरूम उगाने के लिए खाद तैयार करते हैं, जिससे ना केवल पराली का सही उपयोग होता है, बल्कि यह घर के भोजन के उत्पादन में भी मदद करता है।

स्वस्थ जीवनशैली के लिए एक संघर्ष

इस अनोखे घर का निर्माण पीटर और नीनो के व्यक्तिगत संघर्ष से प्रेरित है। नीनो को रक्त कैंसर का पता चला था और कीमोथेरेपी के बाद उनके फेफड़े दिल्ली की प्रदूषित हवा से निपटने में संघर्ष कर रहे थे। एक डॉक्टर ने उन्हें दिल्ली छोड़ने की सलाह दी थी, लेकिन एक आयुर्वेदिक विशेषज्ञ ने उन्हें जैविक जीवनशैली अपनाने की सलाह दी। इसके बाद उन्होंने गोवा में कुछ समय बिताया और फिर दिल्ली लौटकर अपने घर को एक स्वास्थ्यपूर्ण और आत्मनिर्भर स्थान में बदलने का संकल्प लिया।

आज, यह घर हरित जीवनशैली का एक बेहतरीन उदाहरण बन चुका है, जो प्राचीन तकनीकों और आधुनिक पर्यावरणीय उपायों का संयोजन है। यह घर दिल्ली जैसे प्रदूषित शहर में एक नखलिस्तान के रूप में खड़ा है, जहां स्वच्छ हवा, सौर ऊर्जा, जल संरक्षण और जैविक खेती के जरिए एक स्वस्थ और आत्मनिर्भर जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है।

15,000 पौधों से स्वच्छ हवा

इस घर में लगाए गए 15,000 पौधे हवा की गुणवत्ता को बनाए रखते हैं। इन पौधों की मदद से घर का त्त्छ 10-15 के बीच रहता है, जो दिल्ली के प्रदूषण स्तर के मुकाबले बेहद कम है। हर एक पौधा घर के अंदर स्वच्छ हवा प्रदान करने में योगदान देता है।

आत्मनिर्भर ऊर्जा और जल प्रबंधन

यह घर पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होता है, यानी ये घर बाहरी बिजली आपूर्ति पर निर्भर नहीं है। सौर पैनलों के जरिए यह घर अपने सारे ऊर्जा जरूरतों को पूरा करता है। जल संरक्षण के मामले में भी यह घर पूरी तरह से आत्मनिर्भर है। यहां वर्षा जल को एकत्र करने के लिए 15,000 लीटर के टैंक का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे घर में पौधों की सिंचाई की जाती है। पानी का पुनः उपयोग भी किया जाता है, ताकि कोई भी बूंद व्यर्थ न जाए।

खुद का भोजन उगाने की क्षमता

दिल्ली जैसे प्रदूषित शहर में यह घर न केवल हवा में सुधार करता है, बल्कि यहां के निवासी अपना भोजन भी खुद उगाते हैं। पीटर और नीनो अपने घर में जैविक तरीके से सब्जियां उगाते हैं, जिससे उन्हें बाजार से सब्जियां खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। वे साल भर जैविक और सतत (सस्टेनेबल) खेती के तरीके अपनाते हैं।

चलती एंबुलेंस में हुआ नाबालिग से रेप

पूरी रात बंधक बनाकर रखा... दरिंदगी में दीदी और जीजा भी थे शामिल !

नेशनल डेस्क. मध्य प्रदेश में बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक 16 साल की लड़की के साथ कथित तौर पर बलात्कार किया गया। यह घटना मऊगंज जिले की है जहां 22 नवंबर को %108% इमरजेंसी सर्विस के तहत संचालित की जा रही चलती एम्बुलेंस में लड़की के साथ रेप हुआ। इस दौरान ड्राइवर समेत 4 लोग और मौजूद थे। गुरुवार को मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस ने ड्राइवर सहित चार आरोपियों में से दो को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस सब के बीच उप महानिरीक्षक (रीवा रेंज) साकेत पांडे ने कहा, लड़की अपनी बहन और जीजा के साथ एम्बुलेंस में यात्रा कर रही थी (उनमें से कोई भी मरीज नहीं था)। एंबुलेंस में तीनों के अलावा,ड्राइवर और उसका एक सहयोगी थे। पांडे ने इसके बारे में बात करते हुए कहा कि नाबालिग लड़की अपनी बहन और जीजा के साथ, एम्बुलेंस में जा रही थी जिसका ड्राइवर उन्हें जानता था। इस दौरान रास्ते के बीच लड़की की बहन और उसका जीजा पानी लाने के बहाने गाड़ी से उतर गए, उसी वक्त ड्राइवर ने तेजी से एंबुलेंस चला दी। इसके बाद सुंसन गांव में चलती एम्बुलेंस में ड्राइवर के हेल्पर राजेश केवट ने लड़की के साथ बलात्कार किया। इस बारे में बात करते हुए ष्ठद्धत्त ने बताया कि लड़की को पूरी रात बंधक बनाकर रखा गया था। अगली सुबह उसे सड़क किनारे फेंक दिया गया। घर पहुंचने के बाद, पीड़िता ने अपनी आपबीती अपनी मां को सुनाई, जो इस डर से दो दिनों तक पुलिस के पास नहीं गई कि घटना से परिवार की बदनामी हो जाएगी। बताया जा रहा है कि लड़की की बहन और उसके जीजा पर भी इस घिनोने अपराध में सहायता करने का आरोप है। पांडे ने इस मामले में आगे कि जानकारी देते हुए बताया कि 25 नवंबर को पीड़िता और उसकी मां ने हिम्मत करते हुए पुलिस से कॉन्टैक्ट किया, जिसने उनकी शिकायत पर कथित बलात्कारी (केवट) सहित चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। उन्होंने कहा कि दो आरोपियों, एम्बुलेंस चालक वीरेंद्र चतुर्वेदी और उसके सहयोगी केवट को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया गया है जबकि लड़की की बहन और जीजा फरार हैं। IPS अधिकारी ने कहा कि लड़की की बहन और जीजा को पकड़ने के लिए तलाश शुरू कर दी गई है। सभी आरोपियों पर यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

मैक्रों ने पहली बार कबूला- 1944 में फ्रांसीसी सैनिकों ने अफ्रीकी सैनिकों का किया नरसंहार

इंटरनेशनल डेस्क: फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने बृहस्पतिवार को सेनेगल के प्राधिकारियों को लिखे एक पत्र में पहली बार माना है कि 1944 में फ्रांसीसी सेना द्वारा पश्चिम अफ्रीकी सैनिकों की हत्या नरसंहार थी। मैक्रों का यह बयान सेनेगल की राजधानी डकार के बाहरी इलाके में स्थित मछुआरों के गांव थियारोये में द्वितीय विश्व युद्ध में हुई हत्याओं की 80वीं बरसी की पूर्व संध्या पर आया है। फ्रांस के 1940 में हुए युद्ध के दौरान फ्रांसीसी सेना की तरफ से लड़ने वाले पश्चिम अफ्रीका के 35 से 400 सैनिकों को फ्रांसीसी सैनिकों ने ही एक दिसंबर 1944 को मार डाला था।

फ्रांस के लोगों ने इसे अवैतनिक वेतन के मुद्दे पर हुआ विद्रोह बताया था। पश्चिमी अफ्रीका के लोग तिरालेउर्स सेनेगलैस नाम की एक इकाई के सदस्य थे, जो फ्रांसीसी सेना में औपनिवेशिक पैदल सेना की एक टुकड़ी थी। इतिहासकारों के अनुसार, नरसंहार से कुछ दिन पहले भुगतान न किए गए वेतन को लेकर विवाद था, लेकिन एक दिसंबर को फ्रांसीसी सैनिकों ने पश्चिम अफ्रीकी सैनिकों को घेर लिया और गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। सेनेगल के राष्ट्रपति बासिरू डियोमाये फे ने कहा कि उन्हें मैक्रों का पत्र मिला है।

फे ने बृहस्पतिवार देर रात संवाददाताओं से कहा कि मैक्रों के कदम से दरवाजा खुलना चाहिए ताकि थियारोये की इस दर्दनाक घटना के बारे में पूरी सच्चाई आखिरकार सामने आ सके। उन्होंने कहा, हम लंबे समय से इस कहानी को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि इस बार फ्रांस की प्रतिबद्धता पूरी, स्पष्ट और सहयोगात्मक होगी। मैक्रों के बयान में कहा गया है, ''फ्रांस को यह स्वीकार करना चाहिए कि उस दिन, अपने पूर्ण वैध वेतन का भुगतान करने की मांग करने वाले सैनिकों और राइफलमैन के बीच टकराव ने घटनाओं की एक श्रृंखला शुरू कर दी, जिसके परिणामस्वरूप नरसंहार हुआ।

अमेरिका में डेमोक्रेटिक सांसदों को उनके घर बम से उड़ाने की मिली धमकी

इंटरनेशनल डेस्क: अमेरिका में कनेक्टिकट से डेमोक्रेटिक पार्टी के चार सांसदों को बृहस्पतिवार को उनके घरों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। यह जानकारी सांसदों और उनके कार्यालयों ने साझा की। जानकारी के अनुसार, प्रतिनिधि सभा के सदस्य जिम हिम्स, जो कोर्टनी, जॉन लार्सन, और जहाना हेस* ने इस तरह की धमकियां मिलने की पुष्टि की है। हालांकि, पुलिस ने इन सांसदों की संपत्तियों पर विस्फोटक सामग्री का कोई सबूत नहीं पाया है। राज्य से प्रतिनिधि सभा के पांचवें डेमोक्रेटिक सदस्य रोसा डेलाउरो और कनेक्टिकट से पार्टी के दो सीनेटरों को भी धमकियां मिली हैं या नहीं, इस बारे में अब तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है।इससे पहले बुधवार को अमेरिका में कैबिनेट स्तर के मनोनीत और शीर्ष प्रशासनिक पदों पर नियुक्त अधिकारियों और उनके परिवारों को भी धमकियां मिलने की खबरें आई थीं। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रवक्ता ने बताया कि कानून प्रवर्तन एजेंसियां इन धमकियों को गंभीरता से ले रही हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही हैं। फिलहाल धमकियों के स्रोत और मकसद का पता लगाने के लिए जांच जारी है। अधिकारियों ने कहा कि वे सुरक्षा को लेकर अतिरिक्त सतर्कता बरत रहे हैं और स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं।

पूर्वी युगांडा में भूस्खलन ने मचाई तबाही, 15 लोगों की मौत, 113 लापता

नैरोबी: पूर्वी युगांडा के छह गांवों में भूस्खलन के कारण कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई तथा 113 अन्य लापता हैं। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार 15 घायल लोगों को बचा लिया गया है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। युगांडा रेड क्रॉस सोसाइटी ने बृहस्पतिवार को बताया कि भूस्खलन में 40 घर नष्ट हो जाने के बाद 13 शव बरामद किए गए तथा बचाव कार्य अभी जारी है। स्थानीय मीडिया ने बताया कि अधिकारियों को आशंका है कि मृतकों की संख्या बढ़कर 30 तक हो सकती है। बुधवार रात भारी बारिश के बाद पहाड़ी जिले बुलाम्बुली में भूस्खलन हुआ। यह जिला राजधानी कंपाला से लगभग 280 किलोमीटर पूर्व में है। क्षेत्र के एक पत्रकार ने एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि स्थानीय अधिकारियों ने कहा है कि बचाव कार्य में सहायता के लिए भारी मशीन लाई जाएगी, लेकिन सड़कों पर कीचड़ है और अब भी बारिश हो रही है। %डेली मॉनिटर% समाचार पत्र ने बताया कि अब तक बरामद अधिकांश शव बच्चों के हैं। इस बीच बुधवार को पाकवाच पुल के जलमग्न होने के बाद नील नदी में चलाए गए बचाव अभियान के दौरान दो नौकाएं पलट गईं।

अमेरिकी ने अपने नागरिकों के लिए पाकिस्तान यात्रा को लेकर जारी की सख्त एडवाइजरी

पेशावर. अमेरिकी दूतावास ने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत की राजधानी पेशावर में सुरक्षा चिंताओं के मद्देनजर एक सुरक्षा अलर्ट जारी किया है। दूतावास ने अपने नागरिकों से 16 दिसंबर तक इस शहर का दौरा न करने की सख्त सलाह दी है। इस सुरक्षा अलर्ट का शीर्षक सेरेना होटल, पेशावर को खतरा है, जिसमें विशेष रूप से अमेरिकी नागरिकों को इस क्षेत्र में यात्रा करने से बचने और अपनी यात्रा योजनाओं पर पुनर्विचार करने की सलाह दी गई है। अमेरिकी दूतावास के कर्मचारियों को भी होटल जाने से बचने की चेतावनी दी गई है। दूतावास ने अपनी घोषणा में कहा, ''अमेरिकी नागरिकों को इस अवधि के दौरान सेरेना होटल और इसके आसपास के क्षेत्रों में जाने से बचने की सलाह दी जाती है, और उन्हें अपनी यात्रा योजनाओं पर पुनर्विचार करने के लिए कहा जाता है।इसके अलावा, यह भी कहा गया कि अमेरिकी नागरिकों को सितंबर में जारी किए गए एक अन्य परामर्श की याद दिलाई जाती है, जिसमें चेतावनी दी गई थी कि खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में आतंकवाद और सुरक्षा के मुद्दों के चलते यात्रा करने से बचना चाहिए। पेशावर का सेरेना होटल एक प्रमुख और उच्च सुरक्षा वाले होटल के रूप में जाना जाता है, जिसे विदेशी नागरिकों और दूतावास कर्मचारियों के लिए एक सुरक्षित स्थान माना जाता है। हालांकि, अमेरिकी दूतावास द्वारा जारी इस अलर्ट से यह संकेत मिलता है कि वहां कुछ खतरनाक गतिविधियाँ हो सकती हैं, जो सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती हैं।

अलर्ट में दूतावास ने स्पष्ट रूप से कहा है कि इस क्षेत्र में यात्रा करने से अमेरिकी नागरिकों की सुरक्षा प्रभावित हो सकती है और उन्हें विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी जाती है। अमेरिकी नागरिकों को पहले से जारी सुरक्षा परामर्श का पालन करने और अपने यात्रा कार्यक्रमों पर पुनर्विचार करने के लिए कहा गया है।

हाल के महीनों में पाकिस्तान, विशेषकर खैबर पख्तूनख्वा और उसके आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा की स्थिति बिगड़ी है। आतंकवादी हमलों और सुरक्षा संबंधित घटनाओं के कारण कई देशों के दूतावासों ने अपने नागरिकों को इन क्षेत्रों में यात्रा करने से परहेज करने की सलाह दी है। यह सुरक्षा अलर्ट इस बात का संकेत है कि अमेरिकी दूतावास अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर गम्भीर है और खतरों को देखते हुए उपयुक्त कदम उठा रहा है।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक श्रीमती ज्योती मिश्रा द्वारा कॉम्पेक प्रिंटर्स प्रा. लि. फ्री प्रेस हाउस 3/54, प्रेस कॉम्पलेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 45ए गुप्ता चैम्बर पहली मंजिल जावरा कंपाउंड इंदौर, (म.प्र.) से प्रकाशित।
प्रधान सम्पादक : अशीष मिश्रा आर.एन.आई. पंजीयन क्रमांक : एमपी/एच/आइएन 2009/34385 फोन नं : 0731-4202569 फैक्स नं : 0731-4202569